डाक पंजीयन 29/2010-2012

सीधी और सच बात, साहस के साथ

आज की जनधारा

पेज-06

वेब संस्करण
www.aajkijandhara.com
www.jandhara.in
Jandhara24x7
@AJandhara/Jandhara24/7
AajkiJandhara & Jandhara24x7
6232949114, 8959444440

RNI No.- 52143/91

वर्ष : 35, अंक : 189, रायपुर, मंगलवार 14 जुलाई 2026

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, मध्यप्रदेश व नई दिल्ली से प्रकाशित epaper www.aajkijandhara.com | email:aajkijandhara@gmail.com | अषाढ़ कृष्ण पक्ष-15, वि.सं. 2083 | पृष्ठ : 12 | मो. : 9425203900, 9425243430 मूल्य: 2.00 रु.

ब्रीफ न्यूज

आईईडी विस्फोटः एक जवान बलिदान, 4 घायल

कोहिमा। नगालैंड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। जहां चुमौकेदिमा इलाके में आज एक संदिग्ध बम धमाका हुआ। इस हमले में असम राइफल्स के एक जवान देश के लिए बलिदानी हो गए, जबकि चार अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं। अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यह एक संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट था।

व्हाट्सएप-टेलीग्राम के लिए तय होंगे नए नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम द्वारा उनके उपयोगकर्ता नाम आधारित मैसेजिंग सुविधाओं पर जारी किए गए नोटिसों पर प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहा है, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कोई भी नियामक ढांचा सभी प्लेटफॉर्मों पर समान रूप से लागू होगा। सोमवार को एक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मंत्रालय को व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया मिली थी और कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने से पहले ही इसकी समीक्षा की जा रही थी।

जून में लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ी

नई दिल्ली। आलू-अदरक समेत खाने-पीने की चीजों के दाम फिर बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार छठे महीने बढ़ी है। महंगाई बढ़कर जून में 4.38फीसदी पर पहुंच गई है। जनवरी से लगातार रिटेल महंगाई दर बढ़ रही है। तब यह 2.74फीसदी थी। फूड इन्फ्लेशन जून में बढ़कर 5.32फीसदी पर पहुंच गई है। मई में यह आंकड़ा 4.38फीसदी पर था। जनवरी 2025 के बाद यह पहला मौका है जब महंगाई रिजर्व बैंकके 4फीसदी के मिडपॉइंट टारगेट के पार निकल गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज 13 जुलाई को ये आंकड़े जारी किए।

विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर हंगामा

● भूपेश बोले- लोगों ने चंदा दिया, डकैती पड़ गई, रमन बोले- राज्य का विषय नहीं, कार्यवाही स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायक चंदा चोरी के पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि रामभक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी जारी रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें डकैती पड़ गई। लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रश्नकाल में डीएड-बीएड कॉलेज का मुद्दा गूंजाः इससे पहले प्रश्नकाल में भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड-डीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल किया। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू है। बीएड-डीएड शेष पृष्ठ 10 पर

डॉ. तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि

● सीएम साय ने पंडवानी गायिका को बताया छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान

रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वरिष्ठ विधायकों ने तीजन बाई के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी विलक्षण प्रतिभा से लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। पात्रों का सजीव चित्रण, ओजपूर्ण वाणी और प्रभावशाली प्रस्तुति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का जीवन संघर्ष, साधना और समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। जिस दौर में महिलाओं की पंडवानी गायन में शेष पृष्ठ 10 पर

प्रदेश में पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

● गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में 50-50 सीटों पर होगा प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होने जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने राज्य के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इन कॉलेजों में 50-50 एमबीबीएस सीटें स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 250 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ जाएंगी।

जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, उनमें गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम शामिल हैं। सभी कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने आवेदन, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद इन कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) जारी किया है। इसके बाद अब इन कॉलेजों में 2026-27 सत्र से प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।

एमपी में 1160 करोड़ का चावल घोटाला

गरीबों के पोषण का अनाज एथेनॉल के नाम पर हुआ गायब

भोपाल। अजब-गजब मध्य प्रदेश में अब एक ऐसा कथित एथेनॉल घोटाला सामने आया है, जिसने पूरे सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया है। हद यह है कि इस खेल में शामिल घोटालेबाज सरकार से ही भारी सब्सिडी पर चावल खरीदकर वापस उसे नए नाम से सरकार को ही बेच रहे थे। सबसे बड़ी परेशानी और चिंता की बात यह है कि यह कोई सामान्य अनाज नहीं, बल्कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए तैयार किया गया फोर्टिफाइड चावल था। बालाघाट में एक ट्रक की धरपकड़ से शुरू हुआ यह मामला अब करीब 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल की हेराफेरी और 1160 करोड़ रुपये के संभावित घोटाले की विस्तृत जांच तक पहुंच गया है।

एक ट्रक की संदिग्ध मौजूदगी ने खोली महाघोटाले की परतें: इस पूरे कथित घोटाले की शुरुआत 3 जून 2026 को हुई। अधिकारियों को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि सरकारी चावल से भरे तीन ट्रक बालाघाट जिले के भारतीय खाद्य निगम के नवेगांव गोदाम से छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजे एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल संयंत्र के लिए रवाना हुए थे। इनमें से एक ट्रक, जिसका नंबर सीजी 04 जेडी 3147 था, उसमें 490 बोरी सरकारी चावल लदा था जिसका कुल वजन 242.55 क्विंटल था।

मौसम और भोजन का बहाना बना संदेहास्पद: जांच अधिकारियों ने जब ट्रक के चालक से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि वह सिर्फ भोजन करने अपने घर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ राइस मिल के मालिकों ने कहानी गढ़ी कि अचानक बारिश शुरू होने के कारण ट्रक को मिल परिसर के भीतर सुरक्षित खड़ा किया गया था। हालांकि, जांच अधिकारियों को ये दोनों ही जवाब पूरी तरह संदेहास्पद और मनगढ़ंत लगे।

एक ही चावल के लिए सरकार ने कैसे कर दिया दो बार भुगतान: केंद्र सरकार की नीति के तहत पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी गोदामों में रखे अतिरिक्त चावल को रियायती दरों पर एथेनॉल निर्माताओं को दिया जाता है।

हम होर्मुज के रखवाले, निगरानी के लिए मिलना चाहिए पैसाः ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और तेल आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा और इसके बदले उसे पेमेंट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका लंबे समय से इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभाता रहा है, इसलिए उसकी इस जिम्मेदारी की भरपाई भी होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बहुत बुरे लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन ईरान ने उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा करता है, तो इसके लिए उसे उचित भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का गार्जियन (संरक्षक) बनेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति में कोई बाधा न आए। ट्रंप के अनुसार, दुनिया के लिए इस जलमार्ग की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले देशों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वेस्ट एशिया में एक बड़ा रणनीतिक मोर्चा बनकर सामने आया है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल समुद्री मार्ग से गुजरता है। ट्रंप के इन बयानों को अमेरिका-ईरान संबंधों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।

2020 दिल्ली दंगा मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी

● आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला, 6 आरोपी बरी

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपितों को दोषी करार दिया, जबकि छह आरोपितों को बरी कर दिया।

कौन हुए दोषी और कौन हुए निर्दोष?: दोषी ठहराए गए आरोपितों में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी।

ताहिर हुसैन पर कौन से लगे आरोप?: अदालत ने ताहिर हुसैन को सरकारी आदेश की अवहेलना, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण, हत्या तथा गैरकानूनी जमाव के साझा उद्देश्य से अपराध करने के आरोपों में दोषी ठहराया। हालांकि, उन्हें आपराधिक साजिश रचने और अपराध के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया।

नाजिम को भी सरकारी आदेश की अवहेलना, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण, हत्या तथा शेष पृष्ठ 10 पर

अब शिक्षा में क्रांति का समय : राहुल

● सरकार और शिक्षा मंत्री पर लगाए आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब बेईमान वसूली का तंत्र बन गई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों से अपने दूसरे संवाद से पहले यह बात कही।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि दोनों ने जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा?: राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमानी- ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सच यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।

कांग्रेस नेता ने क्या आरोप लगाए?: उन्होंने शेष पृष्ठ 10 पर

नरोत्तम मिश्रा मंच पर ही रो पड़े, मोहन यादव ने संभाला

भोपाल। दतिया उपचुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का गम कम नहीं हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने समर्थकों को संभालने के बाद नरोत्तम मिश्रा सोमवार को अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और मंच पर ही उनके आंसू निकल पड़े। भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के लिए आयोजित रैली में भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री मोहन यादव संभालते नजर आए।

नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के समर्थन में मंच से भाषण देते समय ही भावुक हो गए। उन्होंने तिवारी को जितवाने के लिए एक-एक घर जाने की बात कही। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाते तिवारी के कंधे पर राख रखा और भावुक हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 16 तारीख से खुद यहीं डेरा जमाएंगे। एक एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा। एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जितवाऊंगा। इतना कहते ही वह भावुक हो गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीट से खड़े होकर नरोत्तम को सहारा दिया। मंच पर कुछ और लोग भी भावुक हो गए। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा में फूट है।

राममंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की भर्ती, एसआईटी की रिपोर्ट मांगी

● सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी; आठों आरोपी 14 दिन और जेल में रहेंगे

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं।

कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में स्ढ्ढ्र के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है।

इधर, राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन की अंतिम डेट 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया।

गुजरात में फैला चांदीपुरा वायरस

एक महीने में 12 बच्चों की मौत, 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव

● मक्खी से फैलती है बीमारी, वैक्सीन भी नहीं बनी

गोधरा। गुजरात में संक्रमण से एक महीने में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से तीन बच्चे चांदीपुरा वायरस से संक्रमित थे। अन्य 9 बच्चों की मौत भी इसी वायरस से होने की आशंका है। हालांकि, इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। संक्रमण के मामले गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली और पंचमहल जिलों में सामने आए हैं।

सरकार ने वायरस से 3 मौतों की पुष्टि की: स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने इस स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि इस घातक वायरस के संक्रमण के कारण अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 बच्चों की मौत गोधरा और राजस्थान के एक बच्चे की मौत हिम्मतनगर में हुई। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वायरस के संदिग्ध लक्षणों वाले 9 अन्य बच्चों की मौत: हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में चांदीपुरा के शेष पृष्ठ 10 पर

पारदर्शिता पर सवाल सोने-चांदी के आभूषणों के रिकॉर्ड पर उठे सवाल, आस्था के खजाने का हिसाब मांग रहा बस्तर

दंतेश्वरी मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल

कृष्ण कुमार सिकंदर

रायपुर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और उससे जुड़े रिकॉर्ड को लेकर उठे विवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर के खजाने और चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए जा रहे सोने-चांदी के आभूषण, नकद राशि और अन्य चढ़ावे के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आरोप लगाया है कि मंदिर में जमा आभूषणों और संपत्तियों का पूरा विवरण वर्षों से सामने नहीं लाया गया है। वहीं, इस मामले में की गई शिकायत की जांच भी लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है।

बस्तर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मां दंतेश्वरी मंदिर का महत्व केवल स्थानीय आस्था तक सीमित नहीं है,

बल्कि यह देशभर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। रियासतकालीन परंपराओं से जुड़े इस मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद राशि, सोने-चांदी के आभूषण, मुकुट, छत्र और अन्य कीमती वस्तुएं अर्पित करते हैं। यही वजह है कि मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों के रखरखाव को लेकर पारदर्शिता की मांग समय-समय पर उठती रही है।

मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्षों से जमा हो रहे आभूषणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मंदिर में मौजूद आभूषणों का रिकॉर्ड केवल उनके वजन तक सीमित है, जबकि उनकी गुणवत्ता, शुद्धता और वास्तविक स्थिति की जांच की कोई स्पष्ट व्यवस्था नजर नहीं आती। उन्होंने मांग की है कि मंदिर के खजाने का वैज्ञानिक तरीके से सत्यापन कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई संपत्तियां किस स्थिति में हैं। पुजारी के अनुसार, वर्ष 2020 में मंदिर के खजाने के सत्यापन को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में देरी उचित नहीं है। मंदिर में चढ़ने वाली हर वस्तु जनता की श्रद्धा से जुड़ी होती है, इसलिए उसका रिकॉर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होना चाहिए।

मां दंतेश्वरी मंदिर सहित बस्तर क्षेत्र के 22 मंदिरों का संचालन टेंपल कमेटी के माध्यम से किया जाता है। इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजन, पूजा व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रबंधन और रखरखाव का काम इसी व्यवस्था के तहत संचालित होता है। हर वर्ष इन मंदिरों में बड़ी मात्रा में चढ़ावा आता है, जिसका उपयोग धार्मिक गतिविधियों और मंदिर प्रबंधन में किया जाता है। ऐसे में मंदिर की आय और संपत्ति के नियमित ऑडिट की मांग अब और मजबूत हो रही है।

श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शी व्यवस्था केवल आर्थिक हिसाब-किताब का विषय नहीं है।

हवाई किराए की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से दो सप्ताह में मांगे नए नियम

नई दिल्ली। हवाई टिकटों के दाम अचानक कई गुना बढ़ जाने की समस्या और शिकायतें के मद्देनजर आज एस लाएंडमीनारायणन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो हफ्तों में कदम उठाने को कहा है। यह मामला यात्रियों के अधिकार , पारदर्शिता और निष्पक्ष किराया निर्धारण से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी विवाद बन गया है।

क्या थी हवाई किराए में अनियमतताओं को लेकर याचिका: भारत में निजी एयरलाइंस बिना पर्याप्त नियमों के डायनेमिक प्राइसिंग अपनाकर यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूल रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एस

लाएंडमीनारायणन बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक जनहित याचिका लगायी गई थी। याचिका की खास मांगें थी। एल्गोरिदम आधारित डायनेमिक प्राइसिंग की निगरानी और नियमन किया जाए। एयर टिकट के किराए में होने वाली अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं। एयरलाइंस द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क (जैसे सीट चयन, सामान, प्राथमिकता सेवाएं आदि) को पारदर्शी बनाया जाए। यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। एक स्वतंत्र विमानन शुल्क और उपभोक्ता संरक्षण आयोग या इसी प्रकार का नियामक निकाय गठित किया जाए। घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के लिए कम-से-कम 25 किलोग्राम मुफ्त चेक-इन बैगेज बहाल करने की मांग भी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों पर गौर करते हुए इस व्यापक जनहित से जुड़ा मामला माना और सुनवाई की। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की। मामले में केंद्र की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उसका अनुवाद किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के सामने भी पेश करना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहचान बनी महतारी वंदन योजना

29 किस्तों में महिलाओं के खातों में पहुँचे 18,805 करोड़ रुपये से अधिक, आत्मनिर्भरता और सम्मान का बढ़ा विश्वास

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक जीवन जीने की नई शक्ति भी प्रदान कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश के हर जिले में दिखाई दे रहे हैं।

11 जुलाई 2026 को योजना की 29वीं किस्त जारी होने के साथ ही प्रदेश की लाखों पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि सीधे अंतरित की गई।

योजना के प्रारंभ से अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को सीधे उनके खातों में उपलब्ध कराई जा चुकी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने से वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में प्रभावी भागीदारी निभा रही हैं और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं।

प्रदेशभर से मिल रही प्रतिक्रियाएं इस योजना की सफलता की सशक्त कहानी कह रही हैं। बालोद जिले की ग्राम बघमरा निवासी श्रीमती देवकी विश्वकर्मा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों की खरीद तथा सिलाई-कढ़ाई के कार्यों में करती हैं।श्रीमती जामवंती विश्वकर्मा बताती हैं कि यह राशि उनके परिवार के लिए हर महीने एक मजबूत आर्थिक सहारा बन गई है। वहीं श्रीमती राधिका सोनवानी कहती हैं कि योजना की सहायता से वे अपने बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा कर पा रही हैं, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

जशपुर जिले की श्रीमती ज्योति पांडेय के अनुसार अब उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। श्रीमती रेहाना खातून ने योजना से मिली राशि के सहारे अपना छोटा घरेलू व्यवसाय शुरू किया और आज वे स्वयं आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। श्रीमती कविता शर्मा और श्रीमती अंजू शर्मा का कहना है कि नियमित सहायता राशि ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास दिया है तथा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का नया आधार प्रदान किया है।

इसी प्रकार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम डुमरिया की श्रीमती बसंती धुर्वे बताती हैं कि महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त मिलने से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी सहायता मिली है। उनका मानना है कि यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहयोग नहीं देती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती है।

योजना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि उनके हाथों में आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रही है। इससे परिवारों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार और बचत की संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिला है।

प्रदेश की लाखों लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि महतारी वंदन योजना उनके जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा का नया आधार बनी है।

डिजिटल क्रांति –सेवा सेतु से घर बैठे मिल रहा है प्रमाण पत्र

'सेवा सेतु - जनता के द्वार, डिजिटल सरकार' पहल से सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, समय और पैसे दोनों की हो रही बचत

रायपुर। सेवा सेतु छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक डिजिटल सेवाएँ लाने का एक खास पहल है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हर एक नागरिक, विशेषतरू दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों, तक सरकार की योजनाएँ और सुविधाएँ पहुंचाना हैं। श्सेवा सेतुश् सरकार की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। छत्तीसगढ़ शासन की सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस की महत्वाकांक्षी पहल ÷सेवा सेतु - जनता के द्वार, डिजिटल सरकार÷ आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने न केवल सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और त्वरित बनाया है, बल्कि नागरिकों का सिस्टम पर भरोसा भी मजबूत किया है। अब विभिन्न शासकीय प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध डिलीवरी से प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।

कुरूद के सागर की बदली राह, आसान हुआ काम

डिजिटल सेवा के सुगम क्रियान्वयन का ताजा उदाहरण धमतरी जिले के कुरूद तहसील में देखने को मिला। यहाँ के निवासी सागर को अपने एक जरूरी शासकीय कार्य के लिए तत्काल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पारंपरिक प्रक्रिया को याद करते हुए वे बताते हैं कि पहले प्रमाण पत्र बनवाने का मतलब था,कई दिनों की भागदौड़, लंबी लाइनें, दैनिक काम का नुकसान और मानसिक परेशानी। लेकिन सेवा सेतु ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है।

जब सागर को सेवा सेतु पोर्टल की जानकारी मिली, तो उन्होंने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिए। विभाग द्वारा त्वरित डिजिटल सत्यापन के बाद उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया गया, जिसे उन्होंने आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लिया।

सेवा सेतु नागरिकों के लिए अत्यंत हितकारी

सेवा सेतु के तीन मुख्य स्तंभ जिससे जनता को राहत मिली।आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह योजना अत्यंत हितकारी साबित हो रही है, क्योंकि अब उन्हें जिला या तहसील मुख्यालय आने-जाने का किराया और समय नहीं गंवाना पड़ता। डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू होने से शासकीय कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार आया है।

डिजिटल भारत का सपना हो रहा है साकार

सेवा सेतु पोर्टल केवल एक तकनीकी माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-Centric Governance) की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है। सुशासन और पारदर्शिता की इस प्रतिबद्धता ने यह साबित कर दिया है कि यदि तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, तो सरकार सचमुच जनता के द्वार तक पहुँच सकती है। धमतरी के सागर जैसे लाखों नागरिक आज इस व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं।

सहकारी समिति की सुचारू व्यवस्था से खेती की तैयारियां हुईं आसान

समय पर खाद मिलने से किसान गेंद लाल की बढ़ी उम्मीदें

रायपुर। किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के जिला प्रशासन के प्रयासों का लाभ अब सीधे खेतों तक पहुंच रहा है। खैरागढ़ जिले के ग्राम अवेली के किसान गेंद लाल भी उन किसानों में शामिल हैं, जिन्हें खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक उर्वरक समय पर प्राप्त हुआ। इससे उनकी खेती की तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी हो सकीं।

गेंद लाल ने बताया कि उन्हें समिति सलोनी से उनकी पात्रता अनुसार 6 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी, 2 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 1 बोरी पोटाश प्राप्त हुआ। आवश्यक उर्वरक आसानी से उपलब्ध होने के कारण उन्होंने समय पर बुवाई और फसल प्रबंधन का कार्य शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन इस वर्ष समिति में पर्याप्त भंडारण और सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। समय पर खाद मिलने से खेती के प्रति उनका उत्साह बढ़ा है और वे बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं।

जिले में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का परिणाम है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल कृषि कार्यों को गति मिली है, बल्कि किसानों का सहकारी व्यवस्था और प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत हुआ है।

सूडा के नए सीईओ सुमीत अग्रवाल ने संभाला कार्यभार

रायपुर। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के नए सीईओ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के अधिकारी सुमीत अग्रवाल ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने नवा रायपुर में इंद्रावती भवन स्थित सूडा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सूडा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी ली। अग्रवाल इससे पहले दुर्ग नगर निगम के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

सूडा के नए सीईओ सुमीत अग्रवाल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों से कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम सभी

विभागीय अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए काम करेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण करने के दौरान सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, उप संचालक श्रीमती अर्पिता पाठक, अधीक्षण अभियंता रमेश सिंह, सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि और सचित कुमार साहू सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

कैंसर मुक्त भविष्य की ओर धमतरी के कदम

13 से 18 जुलाई तक 14 वर्ष की बेटियों को लगेगा नि:शुल्क जीवनरक्षक टीका

रायपुर। धमतरी जिले में बेटियों को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिले में आज से 18 जुलाई 2026 तक विशेष एचपीवी (HPV) टीकाकरण सप्ताह का आगाज हो गया है। इस महाअभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क जीवनरक्षक HPV टीका लगाया जा रहा है।

कैंसर से बचाव का अचूक और सुरक्षित कवचः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया HPV टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। यह टीका भविष्य में कैंसर के जोखिम को लगभग समाप्त कर देता है, इसलिए सभी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण बेहद जरूरी है।

यहाँ उपलब्ध होगी टीकाकरण की सुविधाः अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने

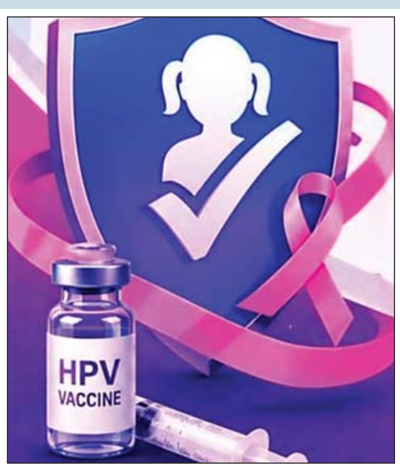

के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC),प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC),जिले के चिन्हित विद्यालय (स्कूल्स) और निर्धारित विशेष टीकाकरण सत्र स्थल पर नि:शुल्क उपलब्ध होगा।

बेटियों का स्वस्थ भविष्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

धमतरी कलेक्टर ने जिले के सभी माता-पिता और अभिभावकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

कलेक्टर ने अपने संदेश में कहा कि बेटियों का स्वस्थ भविष्य हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। HPV टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य विशेषज्ञों पर भरोसा रखकर अपनी 14 वर्ष की बेटियों को यह टीका अवश्य लगवाएं। आपका यह एक छोटा सा निर्णय आपकी बेटी को जीवनभर की सुरक्षा दे सकता है। उन्होंने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वे इसे एक जन-आंदोलन का रूप दें। उन्होंने संकल्प दोहराया कि जिले की एक भी पात्र बालिका इस जीवनरक्षक टीके से वंचित नहीं रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी दिव्यांगजनों के लिए संबल

दो दिव्यांग हितग्राहियों को मिली बैटरी चालित ट्राइसायकल, आवागमन हुआ आसान और आत्मनिर्भरता को मिला बल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग ने दो दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चालित ट्राइसायकल उपलब्ध कराई, जिससे उनके जीवन में नई सहजता और आत्मनिर्भरता आई है।

रायपुर जिला के विकासखंड आरंग के ग्राम निवारी निवासी नंद किशोर टंडन तथा ग्राम सेजा निवासी खिलेन्द्र कुमार साहू (वर्मा) दोनों 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं। आवागमन में होने वाली गंभीर कठिनाइयों के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने दोनों प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें बैटरी चालित ट्राइसायकल प्रदान की।

बैटरी चालित ट्राइसायकल मिलने से अब दोनों हितग्राहियों के लिए दैनिक आवागमन, शासकीय कार्यालयों तक पहुंच, आवश्यक कार्यों का निष्पादन तथा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आसान हो गई है। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और जीवन की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार आया है।

दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से उनकी समस्या का त्वरित समाधान हुआ। इस सहायता से अब वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपने आवश्यक कार्य आसानी से कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रदेशभर में पात्र हितग्राहियों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह व्यवस्था नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करने के साथ-साथ शासन की जनहितैषी और जवाबदेह कार्यप्रणाली को भी सशक्त बना रही है।

पुनर्वासित परिवारों तक पहुंची खाद्य सुरक्षा की गारंटी

पुनर्वास केंद्र पहुंचकर खाद्य विभाग ने किया राशन कार्डों का ई-केवाईसी

रायपुर। पुनर्वासित (विस्थापित या स्थानांतरित) परिवारों को खाद्य सुरक्षा का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें आधार-सीडेड राशन कार्ड (आधार और ई-केवाईसी अपडेटेड) के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसके तहत उन्हें हर महीने पात्र श्रेणी के अनुसार 5 किलो से 35 किलो तक मुफ्त खाद्यान्न का अधिकार प्राप्त है।

बीजापुर जिले में पुनर्वासित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने मैदानी स्तर पर पहल की है। कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन और जिला खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम ने पुनर्वास केंद्र पहुंचकर सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का ई-केवाईसी पूरा किया।

कार्यालयों के चक्कर से मिली राहत

अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने हितग्राहियों के जरूरी दस्तावेजों का मौके पर ही सत्यापन किया और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई। इससे पुनर्वासित परिवारों को ई-केवाईसी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नियमित राशन उपलब्ध कराने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया।

समय पर मिलेगा राशन

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-केवाईसी पूरा होने से राशन कार्ड अद्यतन रहेंगे। इससे हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से समय पर खाद्यान्न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग लोगों को समय पर ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

विभाग ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में आगे भी जिले के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

करोड़ों का शिक्षा बजट, सीखने का स्तर कमजोर

प्रदेश में छह साल बाद एनईपी की रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू हुए छह वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और बुनियादी साक्षरता को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन बच्चों की सीखने की क्षमता और शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर तस्वीर अब भी संतोषजनक नहीं दिख रही है। राज्य में एनईपी के क्रियान्वयन पर तैयार हुई विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट ने शिक्षा तंत्र की उपलब्धियों के साथ-साथ कई गंभीर चुनौतियों को भी उजागर किया है।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह वर्षों में शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर लगभग 1404 करोड़ रुपये खर्च किए गए। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस राशि की व्यवस्था की, लेकिन इतने बड़े निवेश के बावजूद बच्चों के सीखने के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा में केवल भवन, योजनाएं और बजट पर्याप्त नहीं होते, बल्कि कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता ही वास्तविक परिवर्तन का आधार बनती है।

वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो एनईपी के तहत कुल 327.67 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने लगभग 60 प्रतिशत और राज्य सरकार ने करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी निभाई। इस राशि को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया गया। सबसे अधिक निवेश कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा पर हुआ, जहां विद्यार्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से 404 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। वहीं निपुण भारत कार्यक्रम और बुनियादी साक्षरता से जुड़ी योजनाओं पर भी बड़ी राशि खर्च की गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पर भी उल्लेखनीय निवेश किया गया।

हालांकि रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि जिन क्षेत्रों को शिक्षा सुधार की रीढ़ माना जाता है, वहां अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण पर छह वर्षों में केवल 24 करोड़ रुपये के आसपास राशि खर्च की गई, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर भी निवेश सीमित रहा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिक्षक ही पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं पाएंगे तो नई शिक्षा नीति के उद्देश्य जमीन पर पूरी तरह साकार नहीं हो सकेंगे।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए। स्कूलों में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करने के लिए लगभग 114 करोड़ रुपये की राशि लगाई गई। इसके बावजूद राज्य के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट कक्षाओं और डिजिटल उपकरणों की कमी बनी हुई है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा का लाभ सीमित रूप से ही मिल पा रहा है।

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बदलावों का भी उल्लेख किया गया है। राज्य में 10 हजार से अधिक बालवाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जहां लगभग 18 हजार प्रशिक्षित शिक्षक और कार्यकर्ता बच्चों को खेल आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल हुई है। पहली और दूसरी कक्षा की हिंदी पुस्तकों को 16 स्थानीय तथा चार अंतरराज्यीय भाषाओं में द्विभाषी बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में छात्रों का आधार-बायोमेट्रिक अपडेट होगा

- **सूरजपुर से शुरू, रायपुर में इस महीने होगी शुरुआत, डेटा तैयार, कलेक्टर की अनुमति का इंतजार**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब तेजी से किया जाएगा। राजधानी रायपुर में भी इसी महीने विशेष शिविर शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए विद्यार्थियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। कलेक्टर की अनुमति मिलते ही स्कूलों में शिविर लगाकर बायोमेट्रिक अपडेट का काम शुरू कर दिया जाएगा।

दरअसल, प्रदेशभर में ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है, जिनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है। इसी कड़ी में कई जिलों में संकुल स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 22 स्कूलों में 3 हजार से अधिक विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए जाएंगे। इसमें 5 से 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस समय के साथ बदलते हैं। इसलिए यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार 5 से 15 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आधार का बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। अपडेट नहीं होने पर आधार आधारित कई सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।

डेकाथलॉन के पास निगम की कार्रवाई

- **जलभराव रोकने नाले पर बना अवैध पाटे पर चलाया बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग पर भी जारी रहेगी सख्ती**

रायपुर। रायपुर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। सोमवार को नगर निगम जोन-9 की टीम ने महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-8 में डेकाथलॉन के पास मुख्य मार्ग पर नाले के ऊपर बने अवैध पाटे को जेसीबी से तोड़ दिया। इसके बाद नाले की सफाई कर पानी की निकासी कराई गई। नाले पर बने अवैध पाटे के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था। बारिश के दौरान आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन रही थी। इस कार्रवाई के बाद नाले की सफाई कर जल निकासी का रास्ता साफ किया गया।

इस कार्रवाई के दौरान जोन कमिश्नर राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बारोन बंजारे, उमेश नामदेव और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी मौजूद रहे।

दो दिन पहले पंडरी में भी तोड़ा गया था अवैध पाटा: इससे पहले नगर निगम ने पंडरी के दुर्गानगर में भी जलभराव की समस्या दूर करने के लिए कार्रवाई की थी। पंडरी कपड़ा बाजार स्थित प्रकाश होलसेल मार्केट के सामने नाले पर करीब 100 वर्गफीट में बना अवैध पाटा जेसीबी से तोड़ा गया था। निगम के अनुसार दुकान संचालक ने नाले पर कब्जा कर पाटा बना लिया था, जिससे नाले की सफाई प्रभावित हो रही थी और बारिश में दुर्गानगर बस्ती में पानी भरने की समस्या बढ़ रही थी। इसी अभियान के तहत वीर शिवाजी वार्ड-16 के ब्रम्हदेईपारा में भी नाले के पास बने अतिक्रमण को हटाकर अवैध झोपड़ी तोड़ी गई थी, ताकि जल निकासी बाधित न हो।

रायपुर विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश शर्मा ने संभाला पदभार

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी हुए समारोह में शामिल

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश शर्मा ने सोमवार को रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कार्यभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ओ.पी. चौधरी ने डॉ. जय प्रकाश शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रायपुर के सुनियोजित एवं समग्र विकास में रायपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें विश्वास है कि डॉ. शर्मा के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्राधिकरण की विकास

परियोजनाओं को नई गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

समारोह में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू ने कहा कि डॉ. शर्मा के प्रशासनिक अनुभव, चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक किए गए कार्य तथा सामाजिक सरोकारों का लाभ रायपुर विकास प्राधिकरण को मिलेगा। उनके नेतृत्व में प्राधिकरण की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहितकारी कार्यों को नई दिशा एवं गति मिलेगी।

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. जय प्रकाश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राज्य शासन की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के सुनियोजित विकास, आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं तथा हितग्राही सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा।

रमन सिंह से मिले प्रेमासाई महाराज, धर्म-संस्कृति पर चर्चा

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश डॉ. प्रेमासाई महाराज ने विधानसभा निवास में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच धर्म, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, व्यक्तित्व निर्माण और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। महाराज ने शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं भी दीं। मुलाकात के दौरान डॉ. प्रेमासाई महाराज ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को भारतीय संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं डॉ. रमन सिंह ने नई दिल्ली में भारत निर्माण कॉन्क्लेव-2026 के दौरान मिले सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर सम्मान के लिए महाराज को बधाई दी। उन्होंने समाज में सेवा, सद्भाव, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

बस्तर में शांति-विकास की बदलती तस्वीर पर चर्चा: डॉ. प्रेमासाई महाराज ने बस्तर प्रवास के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी नक्सलवाद की चुनौती से प्रभावित था, वहां अब विकास, शांति और सुरक्षा का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं, सुरक्षा बलों के प्रयासों और लोगों की बढ़ती भागीदारी से सकारात्मक बदलाव आया है। बस्तर में आयोजित दिव्य दरबारों और हिंदू जगाओ शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आध्यात्मिक चेतना का संकेत है।

छत्तीसगढ़ का पहला पूर्ण एनएबीएच मान्यता प्राप्त आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बना: डॉ. अभिमन्यु हॉस्पिटल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि डॉ. अभिमन्यु आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स की पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के साथ यह छत्तीसगढ़ का पहला पूर्ण एनएबीएच मान्यता प्राप्त आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बन गया है।

अस्पताल में पंचकर्म, दर्द प्रबंधन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, त्वचा रोग, पाइल्स सहित विभिन्न आयुर्वेदिक विशेषज्ञ सेवाएं आधुनिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्रदान की जा रही हैं। अस्पताल का उद्देश्य पारंपरिक आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ जोड़कर मरीजों को सुरक्षित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है।

एनएबीएच की मान्यता अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की सुरक्षा, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम, दवा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कठोर मूल्यांकन के बाद प्रदान की गई है।

करुणा श्री कैंसर हॉस्पिटल बिलासपुर में ओरल कैंसर पर सीएमई आयोजित

रायपुर। दंत चिकित्सकों और ऑन्कोलॉजिस्ट्स को एक मंच पर लाने वाला सीएमई सत्र कल होटल शिवा इन, बिलासपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए), बिलासपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। इस पैनल चर्चा में मौखिक कैंसर की शीघ्र पहचान और प्रबंधन हेतु दंत चिकित्सकों और कैंसर विशेषज्ञों ने विशेष जोर दिया गया।

इस सत्र का संचालन करुणा श्री कैंसर हॉस्पिटल, बिलासपुर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत कसेर और डॉ नीलम लदेर ने किया। उन्होंने चर्चा को एक मरीज की यात्रा के आधार पर संरचित किया – डेंटल चेयर पर पहली जांच से लेकर स्क्रीनिंग, निदान और ऑन्कोलॉजी फॉलो-अप तक की पूरी प्रक्रिया को

दर्शाते हुए।

इस कार्यक्रम में जिले भर से दंत चिकित्सकों और चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया, पैनलिस्ट्स ने नियमित जांच के दौरान दंत चिकित्सकों को किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, समय पर बायोप्सी और रेफरल के महत्व, तथा डेंटल क्लीनिक और ऑन्कोलॉजी यूनिट के बीच घनिष्ठ समन्वय से मरीजों के परिणामों में किस तरह सुधार लाया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. कसेर ने कहा कि दंत चिकित्सक अक्सर मौखिक कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों वाले मरीजों से सबसे पहले संपर्क में आते हैं, जिससे निदान में देरी कम करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ और उपस्थित चिकित्सा बिरादरी द्वारा इसे भरपूर सराहा गया। करुणा श्री कैंसर हॉस्पिटल ने क्षेत्र में शीघ्र कैंसर पहचान हेतु सामुदायिक जागरूकता, स्क्रीनिंग पहल और सहयोगात्मक सीएमई कार्यक्रमों के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई।

तीर्थों की मर्यादा बनाए रखें, उन्हें पिकनिक स्पॉट न बनाएं

- **देवकीनंदन ठाकुर ने श्रद्धालुओं को दिया मैसेज, जयकारों से भक्तिमय हुआ कथा पंडाल**

रायपुर। देवकीनंदन ठाकुर ने श्रीमद्भागवत कथा पर तीर्थों की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा का मैसेज दिया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि, आज लोग तीर्थों को घूमने-फिरने की जगह समझने लगे हैं, जबकि तीर्थ आस्था, साधना और आत्मशुद्धि के केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि तीर्थों को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। वहां की पवित्रता, अनुशासन और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है। जब तीर्थों की मर्यादा टूटती है तो उनकी दिव्यता भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। यदि श्रद्धालु श्रद्धा, स्वच्छता और अच्छे आचरण के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे, तभी तीर्थों की पहचान और आध्यात्मिक महत्व

बना रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि तीर्थ स्थलों पर ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे उनकी गरिमा प्रभावित हो।

गोवर्धन परिक्रमा महोत्सव भी मनाया: कथा में गोवर्धन परिक्रमा महोत्सव भी मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा कर गिरिराज महाराज का स्मरण किया। कथा पंडाल में भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा में भाग लेकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

पूतना प्रसंग का उल्लेख: अपने प्रवचन में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। उन्होंने पूतना प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान भाव देखते हैं। जो व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ छोड़कर सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। उन्होंने माता-पिता के सम्मान को हर संतान का पहला धर्म बताया और कहा कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखने से घर में बार-बार प्रभु का स्मरण होता है।

नकटी गांव से लोकभवन तक पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस

- **15 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर आवेदन सौंपा जाएगा; राजीव भवन में पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा**

रायपुर। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रभावित परिवारों के साथ नकटी गांव से राजभवन (लोकभवन) तक पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है।

राजभवन को रिमाइंडर पत्र भी भेजा गया है। पार्टी को 15 जुलाई को समय मिलने की उम्मीद है। वहीं, पदयात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की और नेताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपीं।

कांग्रेस करेगी कार्रवाई की मांग: कांग्रेस का कहना है कि नकटी गांव में गरीब परिवारों के मकान तोड़े गए हैं और प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए यह पदयात्रा निकाली जाएगी। पार्टी इस पूरे मामले को राज्यपाल के सामने उठाकर कार्रवाई की मांग करेगी।

मीटिंग में ये नेता रहे मौजूद: बैठक में पूर्व प्रदेश

कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, प्रदेश महामंत्री दीपक मिश्रा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, बीरगांव महापौर नंदलाल देवांगन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नकटी गांव में 29 जून को हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इससे पहले पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला कर चुकी है। अब पदयात्रा के जरिए कांग्रेस इस मामले को सड़क से राजभवन तक ले जाने की तैयारी में है।

दिव्यांश फाउंडेशन ने किया नि:शुल्क बैग वितरण

रायपुर। दिव्यांश फाउंडेशन द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला रायपुरा के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत किया गया । जिसमें लगभग पूरे विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क बैग वितरण किया गया। जिससे अन्य बच्चों को आगे बढने का उत्साह बढ़े और बच्चे अच्छे से मेहनत करे । भविष्य में तरक्की कर अपने विद्यालय एवं माता-पिता का नाम रोशन करें। सर्व शिक्षा अभियान सब-पढ़े सब-बढ़े के उद्देश्य से विद्यालय प्रवेश महोत्सव का आयोजन दिनांक 13 जुलाई को किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अग्रसेन आयरन एंड स्टील प्रा. लि. सीएसआर के माध्यम से किया गया । कार्यक्रम को सफल बनाने में मनीष राय, पवन यदु, मुकेश साहू, प्रणव वर्मा और लाखन जायसवाल का विशेष सहयोग रहा।

मैट्स विश्वविद्यालय में एजेंटिक एआई पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर। मैट्स विश्वविद्यालय, आरंग स्थित मैट्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएसईआईटी) के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एजेंटिक एआई) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति डॉ. अमर शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएलएम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान एवं प्रदर्शन सत्र के दौरान एजेंटिक एआई की अवधारणा, संरचना, कार्यप्रणाली, अनुप्रयोगों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्वायत्त निर्णय-निर्माण, कार्यप्रवाह स्वचालन तथा एआई एजेंट्स के वास्तविक जीवन में बढ़ते उपयोग को व्यावहारिक

उदाहरणों के माध्यम से समझाया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. (डॉ.) के. पी. यादव ने विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। निदेशक डॉ. बृजेश पटेल ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएँ विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ने तथा उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विभागाध्यक्ष डॉ. अभिषेक गुरु के नेतृत्व में तथा डॉ. अराधना कुमारी सिंह एवं अन्य संकाय सदस्यों के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एजेंटिक एआई के अनुप्रयोगों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने हैंड्स-ऑन सत्र के माध्यम से आधुनिक एआई टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला में बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर नई तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान अर्जित किया।

वो सात किस्में, जो बनी डिजाइनर राईस...!

स्वाद के साथ सेहत की गारंटी

भाटापारा। गोल्डन राईस, रोकता है रतौंधी जैसी बीमारी। लो- ग्लाईमिक इंडेक्स राईस का सेवन कर सकेंगे मधुमेह रोगी। इंडियन कौंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने विशेष उद्देश्य के लिए चावल की सात ऐसी किस्में विकसित की हैं जिन्हें चडिजाइनर राईसज की श्रेणी में जगह मिली है।

देश में उपलब्ध चावल की अधिकांश किस्में फोर्टीफाइड या बायो फोर्टीफाइड राईस के रूप में हैं। इनमें गोल्डन राईस को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग को देखते हुए विकसित किया गया है। बदलाव के इस दौर में अब छत्तीसगढ़ की स्थानीय किस्में भी ऐसे गुणों की मांग कर रहीं हैं ताकि आयरन, जिंक, प्रोटीन और लो-ग्लाईसेमिक इंडेक्स जैसे गुणों के समावेश की राह आसान हो सके। यह स्थिति यदि बनी तो छत्तीसगढ़ पोषण युक्त प्रीमियम चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य बन सकता है।

शिखर पर गोल्डन राईस

इंडियन कौंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने चावल की जो सात किस्में विकसित की हैं उनमें गोल्डन राईस शिखर पर है। बिटा कैरोटीन से समृद्ध यह चावल विटामिन की कमी दूर करके रतौंधी जैसी

बीमारी पर लगाम लगाता है। एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने में सक्षम है आयरन एवं जिंक फोर्टीफाइड राईस। हाई प्रोटीन राईस नाम है उस चावल का जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित आबादी के लिए विकसित किया गया है।

लो-जी आई राईस

मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत किया गया है, लो- ग्लाईसेमिक इंडेक्स राईस को। रक्त शर्करा धीरे-धीरे बढ़ाता है यह चावल। लाल और काला चावल इसलिए विशेष है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। ब्लैक राईस इसलिए तेजी से पहचान बना रहा है क्योंकि इसका सेवन हृदय को सेहतमंद बनाए रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रसंस्करण के दौरान आयरन फोलिक एसिड और विटामिन- बी2 मिलने के बाद तैयार फोर्टीफाइड राईस पहचान बना चुका है।

संभावित उपयुक्तता

छत्तीसगढ़ की स्थानीय धान की किस्मों जैसे दुबराज, विष्णुभोग, जीराफूल, नागकेसर में उत्कृष्ट स्वाद एवं सुगंध है। इन पारंपरिक किस्मों में भी आयरन, जिंक, प्रोटीन और लो- ग्लाईसेमिक इंडेक्स जैसे गुणों का वैज्ञानिक समावेश किया जाए तो अपना प्रदेश वैश्विक स्तर पर पोषण युक्त प्रीमियम चावल का प्रमुख उत्पादक बन सकता है।

अधिक उत्पादन नहीं पोषण सुरक्षा महत्वपूर्ण

डिजाइनर राईस केवल अधिक उत्पादन का नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा का भविष्य है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सुगंधित धान किस्मों–दुबराज, विष्णुभोग, जीराफूल और नागकेसर–में आधुनिक जैव-सुदृढ़ीकरण (बायोफोर्टिफिकेशन) और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे गुणों का समावेश कर उन्हें वैश्विक प्रीमियम एवं स्वास्थ्यवर्धक चावल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे किसानों की आय, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य और राज्य की विशिष्ट पहचान–तीनों को एक साथ नई दिशा मिलेगी।

डॉ.एस.आर.पटेल, रिटायर्ड साइंटिस्ट (एग्रोनॉमी), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

बाराडोली संकुल में प्रधान पाठक राजेंद्र को भावभीनी विदाई

सम्मान समारोह में शिक्षकों ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

बसना। शासकीय उच्च प्राथमिक शाला धनापाली में पदस्थ प्रधान पाठक राजेंद्र कुमार साहू के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के अवसर पर संकुल केंद्र बाराडोली में संकुल स्तरीय विदाई सह सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षकों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने श्री साहू के लंबे, अनुशासित एवं प्रेरणादायी शैक्षणिक जीवन को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधान पाठक राजेंद्र कुमार साहू थे। अध्यक्षता ग्राम पंचायत बाराडोली के सरपंच वासुदेव धवल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोकेश्वर सिंह कंवर, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक अनिल सिंह साव, नोडल प्राचार्य जानकी जीवन प्रधान तथा समन्वयक खीरसागर खूंटे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर पूजा-अर्चना

एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात सभी अतिथियों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया।

उद्बोधन सत्र में शिक्षक राजेश साहू ने राजेंद्र कुमार साहू के जीवन परिचय का वाचन करते हुए उनके सम्मान में मानपत्र प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में साहू की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासनप्रियता, कार्यकुशलता एवं शिक्षा के प्रति समर्पण की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका सेवाकाल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत रहेगा। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन व्याख्याता ललित मिश्रा ने किया। उन्होंने साहू के अनुकरणीय कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा भविष्य में भी शिक्षा जगत को उनके मार्गदर्शन का लाभ मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर संकुल केंद्र बाराडोली के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों ने राजेंद्र कुमार साहू को शाल, श्रीफल, अंगवस्त्र, डायरी, पेन, श्रीमद्भगवद्गीता, छाता एवं आलमारी भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम के अंत में शासकीय प्राथमिक शाला बाराडोली के प्रधान पाठक नरसिंग खूंटे ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

समारोह को सफल बनाने में नोडल प्राचार्य जानकी जीवन प्रधान, अरुण मिश्रा, ललित मिश्रा, रामजी साव, समीर साहू, अनिता कौशिक, सरस्वती मिश्रा, लता मिश्रा, गौकरण सोनी, वरुण सिदार, चक्रधर भोई, नंदिनी शर्मा, हेमवती पारेश्वर, कामिनी साहू, राजेंद्र जगत, मानस रंजन पुरोहित, नरेश प्रधान, नरसिंग खूंटे, रूपेश बिशी, प्रसन्न प्रधान, राजेश साहू, सहित संकुल के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कौशिल्या को मिली नई राह, करेले की खेती से बढ़ा मुनाफा

महासमुंद। जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम बरतुंगा के कृषक दम्पति कौशिल्या बाई यदु और उनके पति कभी पारंपरिक धान की खेती करते थे, उन्होंने समय के साथ अपनी सोच बदली और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में करेला की आधुनिक खेती अपनाया। साथ ही ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर उन्होंने अपनी आय में इजाफा किया।

कृषक कौशिल्या बाई यदु बताती है कि पूर्व में वे अपने 0.40 हेक्टेयर सिंचित भूमि में मुख्य रूप से धान की खेती करती थीं। धान की खेती से उन्हें अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होती थी, जिससे परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। बेहतर आय की तलाश में उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत करेला की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। उद्यानिकी विभाग की तकनीकी सलाह के

अनुसार उन्होंने ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इन तकनीकों से सिंचाई जल की बचत हुई, खरपतवार नियंत्रण में सुविधा मिली, पौधों की बेहतर वृद्धि हुई तथा उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार आया। विभाग द्वारा करेला फसल एवं सपोर्ट सिस्टम के लिए 13, 600 रुपए की अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदान की गई, जिससे खेती की प्रारंभिक लागत में भी सहायता मिली। श्रीमती यदु बताती है कि करेला की खेती से उन्हें अपेक्षा से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। स्थानीय बाजार एवं पिथौरा मंडी में करेला की अच्छी मांग और उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। खेती में लगभग 40 हजार रुपए की लागत के मुकाबले उन्हें लगभग 1 लाख 45 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। श्रीमती यदु की उपलब्धि ने ग्राम बरतुगा सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों को भी प्रेरित किया है। इससे क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

लंबित करों का तत्काल भुगतान करें, अन्यथा नाम होंगे सार्वजनिकः सीएमओ

महासमुंद। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सौरभ शर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र के समस्त नागरिकों, व्यापारियों, प्रतिष्ठान संचालकों एवं संपत्ति स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित संपत्ति कर, जलकर, समेकित कर, बाजार किराया, यूजर चार्ज एवं अन्य समस्त देयों का तत्काल भुगतान करें। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को वर्तमान में लाखों रुपए की कर एवं शुल्क राशि प्राप्त होना शेष है, जिसके कारण विकास कार्यों एवं नागरिक सुविधाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शर्मा ने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 36 प्रतिशत ही राजस्व वसूली हो सकी थी, जो अत्यंत निराशाजनक रही। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्त नहीं होने से नगर पालिका की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित हुई तथा विकास कार्यों के संचालन में कठिनाइयां आईं। इसी कारण इस वर्ष राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा राजस्व वसूली कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है, जो अधिकारी एवं कर्मचारी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने में असफल रहे अथवा जिनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, उन्हें राजस्व वसूली के कार्य से हटा दिया गया है तथा उनकी जिम्मेदारी अन्य सक्षम कर्मचारियों को सौंपी गई है। आगे भी कार्य के आधार पर ही जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएंगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड में विशेष राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व अमला घर-घर जाकर करदाताओं से संपर्क कर रहा है तथा उन्हें बकाया कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बावजूद जो करदाता बार-बार सूचना एवं अवसर दिए जाने के बाद भी अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके नाम नियमानुसार सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका अपने राजस्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर सक्षम न्यायालय की शरण लेगी तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध सभी वैधानिक कार्रवाई करेगी।

पं.रविशंकर विश्वविद्यालय के मणीशंकर साव ने प्रदेश में हासिल किया आठवां स्थान

बीएससी अंतिम वर्ष मेरिट सूची शामिल

बसना। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा घोषित बी.एस.सी. अंतिम वर्ष (वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2025) की मेरिट सूची में महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। पंडित स्व.जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना के प्रतिभाशाली छात्र मणीशंकर साव ने प्रदेश की मेरिट सूची में आठवां स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय बसना, नगर एवं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी मेरिट सूची के अनुसार उन्होंने कुल 1800 अंकों में से 1392 अंक अर्जित किए हैं।

मणीशंकर साव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने बसना विकासखंड के अपने गृहग्राम देवरी

(पिलवापाली) में कक्षा पहली से दसवीं तक की शिक्षा शासकीय विद्यालय से प्राप्त की। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 92.33 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे संकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद समीपस्थ ग्रामीण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोषगांव से हायर सेकेंडरी की परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर क्षेत्र में टॉपर रहे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पंडित स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना में प्रवेश लिया, जहां श्रीमती आरती साव, गीतिका प्रधान एवं रोशनी गुप्ता के मार्गदर्शन में अध्ययन करते हुए यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की तथा 2024-2 5में स्टूडेट ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया। बसना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.एस. के. साव ने बताया कि मणीशंकर हमारे महाविद्यालय के अत्यंत होनहार एवं मेहनती छात्र हैं। उन्होंने कहा कि बीएससी प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत कुछ कम अंक प्राप्त हुए थे, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन अध्ययन पद्धति को समझने में समय लगता है। इसके बाद मणीशंकर ने द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में आठवां स्थान प्राप्त किया। डॉ.साव ने कहा कि यदि प्रथम वर्ष में भी कुछ और अंक मिल जाते तो उनके विश्वविद्यालय में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त करने की पूरी संभावना थी। उन्होंने मणीशंकर को महाविद्यालय का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी।

अपनी सफलता का श्रेय मणीशंकर साव ने माता पिता श्रीमती उर्मिला साव-सतीश साव,मामा केशव कुमार साव,गुरुजनों एवं महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों,प्राचार्य डॉ.एस.के.साव को दिया। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन,समय का सदुपयोग और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, शिक्षकों, क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

बडिंग एवं ग्राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन

बसना से शिक्षक प्रेमचन्द साव एवं अजय कुमार भोई ने भाग लिया

बसना। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, महासमुंद इकाई द्वारा विज्ञान आश्रम कसेकेरा कोमाखान में बडिंग एवं ग्राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रामीण जनों को बडिंग एवं ग्राफ्टिंग की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डॉ.विश्वास मेश्राम,अध्यक्षछत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, रायपुर एवं डॉ. वाय.के.सोना, सचिव, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा रायपुर ने प्रतिभागियों को बडिंग एवं

ग्राफ्टिंग की वैज्ञानिक विधियों,पौधों के चयन, देखभाल तथा इनके कृषि एवं पर्यावरणीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से कम समय में अधिक उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण फल एवं पौधों का संरक्षण संभव है।

कार्यक्रम में प्रेमचंद साव एवं अजय कुमार भोई, सदस्य, छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, बसना इकाई की विशेष सहभागिता रही। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं ग्रामीण जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पौधों पर बडिंग एवं ग्राफ्टिंग की विधियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया गया तथा स्वयं अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प भी दिलाया गया।

जल संसाधन विभाग का नहर क्षतिग्रस्त

मरम्मत नहीं होने से किसानों की फसल हो जाती है हर साल बर्बाद

बसना। बसना विकासखंड के ग्राम पर्रापाट में जल संसाधन विभाग की नहर पर बनी खेत मार्ग क्रॉसिंग के क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नहर क्रॉसिंग में आई बड़ी दरारों से नहर का पानी लगातार रिसकर आसपास के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे कृषि भूमि के कटाव और खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन विभाग द्वारा अब तक स्थायी मरम्मत नहीं कराए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। किसानों ने अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पर्रापाट स्थित नहर के खसरा क्रमांक 223 पर किसानों के खेतों तक आने-जाने के लिए क्रॉसिंग का निर्माण किया गया था। समय के साथ यह क्रॉसिंग जर्जर हो गई और इसमें कई स्थानों पर गहरी दरारें पड़ गईं। बारिश के मौसम तथा नहर में पानी छोड़े जाने के दौरान इन्हीं दरारों से

बड़ी मात्रा में पानी रिसकर आसपास के खेतों में फैल जाता है। इससे खेतों में जलभराव की स्थिति बनने के साथ-साथ कृषि भूमि का कटाव भी हो रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में नुकसान और अधिक बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वे अपने स्तर पर बोरे, पत्थर तथा अन्य स्थानीय संसाधनों की सहायता से दरारों को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रयास करते रहे हैं, ताकि पानी का रिसाव कम हो सके। हालांकि अब क्रॉसिंग की स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि यह अस्थायी व्यवस्था भी कारगर साबित नहीं हो रही है। लगातार बढ़ती क्षति के कारण किसानों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर की यह क्रॉसिंग गांव के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी मार्ग से किसान अपने खेतों तक पहुंचते हैं और कृषि कार्य करते हैं। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो क्रॉसिंग के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही नहर का पानी लगातार खेतों में पहुंचने से फसलें खराब होने और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाने की आशंका है। समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नहर का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की मांग की गई है, ताकि किसानों की फसल और कृषि भूमि को नुकसान से बचाया जा सके। शिकायत का टोकन क्रमांक डब्ल्यूपी 260700090470 है।

रथ यात्रा से पहले प्लेसमेंट एवं नियमित कर्मचारियों को मिलेगा वेतन

महासमुंद। नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू के निरंतर प्रयासों और शासन स्तर पर लगातार किए गए प्रभावी समन्वय का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अध्यक्ष की पहल पर शासन ने नगर पालिका के प्लेसमेंट एवं नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। इससे रथ यात्रा के पावन अवसर से पूर्व कर्मचारियों के खातों में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नगर पालिका अध्यक्ष साहू ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने लगातार शासन के समक्ष विषय को प्रमुखता से उठाया। संबंधित अधिकारियों से नियमित संपर्क बनाए रखा तथा शीघ्र राशि जारी कराने के लिए निरंतर प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप शासन द्वारा राशि स्वीकृत एवं जारी की गई। अध्यक्ष ने कहा कि रथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व से

पहले वेतन मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा वे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पर्व मना सकेंगे। उन्होंने शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रत्येक विषय पर वे आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे नगर के विकास, स्वच्छता, राजस्व वृद्धि एवं नागरिक सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

डेयरी व्यवसाय से आत्मनिर्भर बन रहे जिले के 15 हजार से अधिक किसान और महिलाएं

रोजाना 39 हजार लीटर से अधिक दूध का हो रहा संग्रहण

महासमुंद। महासमुंद जिला आज छत्तीसगढ़ के प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। जिले में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दिए जाने से हजारों किसानों और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वर्तमान में 15 हजार से अधिक किसान एवं ग्रामीण डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इसे अपनी आजीविका का प्रमुख साधन बना चुके हैं।

ग्राम जोरातराई की महिला पशुपालक भगवती ध्रुव ने बताया कि उन्हें शत प्रतिशत अनुदान में गिर और साहीवाल नस्ल की गाय पशुधन विकास विभाग के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही गायों के लिए मैट भी दिया गया है, जिसमें वे बैठते है। दोनों ही गाय 10-10 लीटर दूध देती हैं। जिसका कुछ भाग वे अपने घर में

उपयोग के लिए रखती हैं तो शेष को गांव के सहकारी समिति में बेंच देती है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। इसी तरह जोरातराई की जया बाई ध्रुव को भी शत प्रतिशत अनुदान में गिर नस्ल की 2 गाय मिली। जिनसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता है। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ मात्रा में दूध वे रख लेती हैं और बाकि को दुग्ध समिति में विक्रय करती है। इस तरह से उनके परिवार को आर्थिक मजबूती भी मिल गई है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सम्हर के सचिव बोधराम पटेल ने बताया कि जोरातराई गांव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ता देख साल 2021 में दुग्ध सहकारी समिति का गठन किया गया। जहां आसपास के गांव सम्हर, बिराजपाली, कौहाकुड़ा, मुड़ागांव, मोंगरापली, लमकेनी, कोटनपाली और सरायपाली से दूध आता है। जिन्हें बीएमसी कौहाकुड़ा भेजा जाता है। वहां से इसको सीलिंग कर देवभोग रायपुर भेज दिया जाता है। जिले के पांचों विकासखंडों से प्रतिदिन हजारों लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है। देवभोग सहकारी समिति सहित विभिन्न डेयरियों को रोजाना 39 हजार लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसानों को नियमित आय का स्त्रोत मिला है।

पशु चिकित्सा सेवाएं की उप संचालक अंजना नायडू ने बताया कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग लगातार प्रयास किया जा रहा हैं। इसी कड़ी में बागबाहरा विकासखंड के ग्राम जोरातराई में आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह की 19 महिलाओं को शत-प्रतिशत अनुदान पर डेयरी इकाइयां स्थापित कराई गईं।

विधानसभा अध्यक्ष ने 20.01 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण

- **आदर्श कृषि उपज मंडी राजनांदगांव प्रदेश की प्रमुख मंडियों में से एक : विधानसभा अध्यक्ष**

राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज आदर्श कृषि उपज मंडी प्रांगण राजनांदगांव में 20 करोड़ 1 लाख 67 हजार रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण, आदिम जाति विकास, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम तथा सांसद संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में आदर्श कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव की मंडी निधि से 2 करोड़ 39 लाख 17 हजार रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं राजनांदगांव विकासखंड की ग्राम पंचायतों में विभिन्न मदों से स्वीकृत 16 करोड़ 32 लाख 98 हजार रूपए की लागत के 181 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 9 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 29 लाख 52 हजार रूपए की लागत से निर्मित 18 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं मंत्री रामविचार नेताम ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 13 क्लस्टर की 51 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से संवाद कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में धान की जगह अन्य फसल लेने वाले किसानों को अरहर और सोयाबीन बीज वितरण किया गया। अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत मिनीमाता महिला स्वसहायता समूह पेण्ड्री को व्यवसाय संचालित करने के लिए 1 लाख 10 हजार रूपए का चेक वितरण किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंडी निधि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना के विकास में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, ताकि गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो और ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आदर्श कृषि उपज मंडी राजनांदगांव प्रदेश की प्रमुख मंडियों में से एक है, जहां किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहां मॉल, सिनेमा, विश्राम गृह, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धर्मकांटा, अनाज एवं सब्जी मंडी जैसी अनेक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के किसान फसल विविधीकरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। धान के साथ-साथ मक्का एवं सोयाबीन जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती अपनाने से किसानों की आय बढ़ेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ कृषि को टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन जिले के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान खेती-किसानी और समृद्ध लोक संस्कृति से है, इसलिए इसे संरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने कहा। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों को खेती के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन एवं उद्यानिकी जैसी कृषि आधारित गतिविधियों को भी अपनाना चाहिए।

'इकरा' की कोशिशों से होनहारों को मिल रही तालीम की रोशनी

भिलाई। इकरा टीचर्स एसोसिएशन की ओर से मुस्लिम समुदाय के होनहार बच्चों का सम्मान समारोह 12 जुलाई रविवार को गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल जुनवानी रोड में आयोजित किया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं में 75 फीसदी और उससे ज्यादा अंक लाने वाले 60 से ज्यादा होनहार बच्चों को अतिथियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर तमाम अतिथियों के साथ 'इकरा' की पहल पर उच्च शिक्षा हासिल कर करियर में सफल युवाओं ने भी अपनी बात रखी। इन युवाओं ने 'इकरा' की इमदाद के लिए आभार जताया।

आयोजन के मुख्य अतिथि अरामको सऊदी अरब के पूर्व एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हाजी शम्सुद्दीन ने 'इकरा' के काम की सराहना करते हुए कहा कि इनकी वजह से कई घरों के बच्चों ने बेहतर तालीम के जरिए अपनी जिंदगी सवारी है। उन्होंने 'इकरा' की इमदाद से आला तालीम हासिल कर रहे युवाओं से अपील की कि आगे जब आप कामयाब हो जाएं तो अपने से कमजोर लोगों का जरूर साथ दें उन्हें आगे बढ़ाएं।

हज से लौटे खुशकिस्मतों ने नवाजा दुआओं से

इस साल हज्जे बैतुल्लाह के मुबारक सफर से लौटने भिलाई के कुछ हाजियों का इकरा तंजीम की ओर से इस्तकबाल किया गया। इन सभी हाजियों ने तालीम को बढ़ावा देने 'इकरा' के कामकाज को सराहा और आगे भी तरक्की के लिए दुआएं की। इनमें हाजी समी अख्तर फारुकी, हाजी अजमेर खान, हाजी एचएस कोया साहब, हाजी युनूस अली, हज्जन सादिया फारुकी, हज्जन शायना परवीन और हज्जन अहलिया कोया शामिल हैं।

75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों का हुआ इस्तकबाल

इस मौके पर होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। इनमें दसवीं बोर्ड में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले होनहारों में अलिना जागीरदार (97.37), अब्दुल खादिर जहां (95.16), फाइजा खान (93.6), जारा अली (92.6), शादाब अहमद (92.01), नौशीन अंसारी (91.5), माहीम सिद्दीकी (91.5), तबस्सुम फातिमा (89),आइजा अफशीं (89.6), मुहम्मद अरफाज कुरैशी (89.3),तहमीना खान (88.83), अयाना फातिमा (86), सैयद असजाद अली (85.5), इसरा खान (85),शाहाब अहमद (84.50), आलिया परवीन (83.6),सुहैब अंसारी (83.16),अलफिया परवीन (83),तौसिफ खान (82.5),रिजा खान (82.5),महताब खान (81.6), शामिल हैं।

पात्र कब्जाधारियों और आवासहीन परिवारों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू

भिलाई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से पट्टे की मांग कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा मानसून सत्र के प्रथम दिवस विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र कब्जाधारियों और आवासहीन परिवारों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक रिकेश सेन ने राजस्व मंत्री से पूछा था कि क्या शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों एवं कब्जाधारियों को भू-स्वामी अधिकार अथवा पट्टा वितरण की कोई योजना विचाराधीन है तथा यह प्रक्रिया कब तक शुरू होगी?

इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पात्रता निर्धारण के लिए सभी जिला कलेक्टरों को 8 मई 2026 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूरा करने की समय-सीमा तय की है। सर्वे के बाद पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वैशाली नगर सहित प्रदेश के अनेक शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार वर्षों से भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह विषय उठाने का उद्देश्य ऐसे परिवारों को कानूनी अधिकार दिलाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। पट्टा मिलने के बाद पात्र परिवारों को अपनी भूमि पर वैधानिक मालिकाना अधिकार मिलेगा। साथ ही बैंक ऋण, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तथा भूमि संबंधी विवादों से राहत जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। हालांकि सरकार ने अभी पट्टा वितरण की अंतिम समय-सीमा घोषित नहीं की है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सदन में दी गई।

छात्रावास के विद्यार्थियों को जीई फाउंडेशन ने दिए स्कूल बैग

भिलाई। सामाजिक संस्थान गोल्डन एम्पथी (जीई) फाउंडेशन ने नवीन शैक्षणिक सत्र के अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित संदीपनी आवासीय बालक छात्रावास, फरीद नगर में निवासरत विद्यार्थियों को स्कूल बैग, नोटबुक, स्टेशनरी तथा खेलकूद सामग्री का वितरण किया। इस दौरान छात्रावास परिसर में विद्यार्थियों के साथ मौजूद लोगों ने वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर छात्रावास के अधीक्षक रवि दुबे, अनुदेशक स्वेच्छा तिवारी एवं छात्रावास के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जीई फाउंडेशन की ओर से प्रदीप पिल्लई और के. वी. विनोद सहित टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम को सफल बनाने में रेखा रामचंद्रन का विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा। जीई फाउंडेशन ने उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जीई फाउंडेशन के संयोजक प्रदीप पिल्लई ने कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षा के साथ-साथ खेल और पर्यावरण संरक्षण भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। हमारा प्रयास है कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक शिक्षा और अवसर की रोशनी पहुंचे।

उल्लेखनीय है कि जीई फाउंडेशन द्वारा इससे पूर्व संजीवनी बालिका छात्रावास में भी छात्राओं को स्कूल बैग, नोटबुक एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया था। संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में निरंतर जनहितकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

मोटिवेशनल स्पीकर को मिला जन्मदिन का खास तोहफा

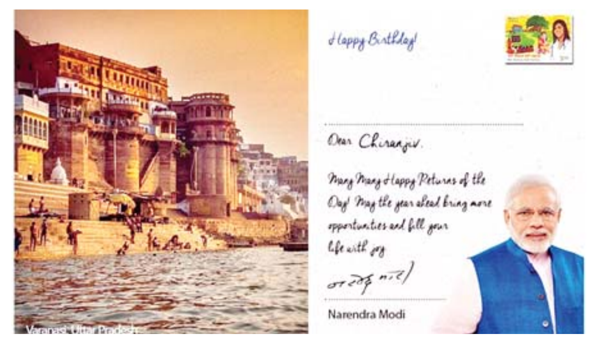

- **प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा बधाई संदेश**

भिलाई। अंचल के शिक्षाविद् और प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर चिरंजीव जैन को उनके जन्मदिन पर खास तोहफा मिला। उन्हें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश सुबह-सुबह सबसे पहले मिला। यह बधाई संदेश मिलने से चिरंजीव जैन बेहद खुश और भावविभोर हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है।

चिरंजीव जैन ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट में राष्ट्रहित में दशक भर से सुझाव देते रहे हैं। जिसमें उनका पूरा ब्यौरा भी दर्ज है। इस सतत संपर्क की वजह से बीते दशक से हर वर्ष 7 जुलाई को उनके जन्मदिन पर सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश मिलता है। उन्होंने जन्मदिन की बधाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। श्री जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से सतत संपर्क की पहल से वे बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि पैरेंटिंग और परीक्षा पे चर्चा जैसी पहल ने देश के करोड़ों बच्चों और पालकों को नई दिशा दी है।

शिवपुरी–जामुल में नशा मुक्त भारत महाअभियान का शुभारंभ

- **रैली एवं नुक्कड़ नाटक से दिया जनजागरण का संदेश**

दुर्ग। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत महाअभियान का शुभारंभ शनिवार को शिवपुरी-जामुल, जिला दुर्ग में जनजागरूकता रैली के साथ किया गया। अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर आमजन को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात प्रमुख चौक-चौराहों पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नशे के दुष्परिणामों का जीवंत चित्रण किया गया।

सायंकाल दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसके उपरांत विभिन्न वक्ताओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामस्वरूप साहू ने कहा कि नशा समाज एवं राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है। इससे परिवार टूटते हैं, युवा शक्ति कमजोर होती है तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। उन्होंने सभी नागरिकों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं संस्कारित समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया।

डॉ. एन. के. सिन्हा, ब्लॉक समन्वयक, ने कहा कि नशे से दूरी बनाकर ही स्वस्थ, सुखी एवं सकारात्मक जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संयोजक डॉ. पी. एल. साव ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की है। दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर ही नशा रूपी राक्षस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों में डिवाइन वर्कशॉप के माध्यम से नशामुक्ति एवं व्यक्तित्व निर्माण संबंधी जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशा धीरे-धीरे मन एवं शरीर को खोखला बनाकर अनेक गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। इससे बचाव के लिए नियमित रूप से महापुरुषों की जीवनियों का स्वाध्याय, योग, अच्छे लोगों की संगति तथा दृढ़ संकल्प को जीवन में अपनाना आवश्यक है।

सदन दुर्ग में जिला साहू संघ व्यापार प्रकोष्ठ का नियुक्ति वितरण व सम्मान समारोह

- **नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगारदाता बनें : दीपक**

दुर्ग। साहू जिला संघ व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक धनंजय लल्लन साहू के नेतृत्व में साहू सदन केलाबाड़ी में नियुक्ति पत्र वितरण व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे दीपक ताराचंद साहू थे। अध्यक्षता साहू जिला संघ अध्यक्ष नंदलाल साहू ने की। जिला पंचायत सभापति प्रिया साहू, कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल साहू और प्रदेश साहू संघ सलाहकार रमेश साहू आदि विशेष अतिथि रहे।

इस मौके पर मुख्य अतिथि दीपक ने व्यापारियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि संगठन में संगठित होना आवश्यक है। संगठन में ही शक्ति है। उन्होंने सभी व्यापरियों से मिलजुलकर लक्ष्य की ओर बढने का आह्वान किया। साथ ही, बिना भेदभाव किए सभी को साथ लेकर आगे बढ़कर समाज को सुदृढ़ करने कहा । वहीं उन्होंने नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि युवाओं को व्यापार कर रोजगारदाता बनने प्रेरित किया। विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साहू ने बेहतर सहयोग करने और व्यापार में बढ़चढ़कर भागीदारी निभाने पर बल दिया। उन्होंने ग्रामोद्योग के माध्यम से व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर दिया। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष नंदलाल ने कहा कि समाज में व्यापार बढने से विश्वास बढ़ेगा और एकजुटता बनी रहेगी। उन्होंने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही।

जिला संयोजक धनंजय साहू ने कहा कि साहू समाज की प्रगति और व्यापार को बढ़ावा देना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने व्यापारियों को एकजुट करने का संकल्प किया। अंत में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं अतिथियों व उत्कृष्ट लोगों का मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।

आईआईआईई ने याद किया सराफ का योगदान

भिलाई। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (आईआईआईई) ने भिलाई चैप्टर के सदस्य और जाने-माने माइनिंग-इंडस्ट्रियल इंजीनियर बिजोय कुमार सराफ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। संस्थान की ओर से के. पटेल ने बताया कि स्व. सराफ ने अपने समर्पण और सक्रिय भागीदारी से सामूहिक मिशन को समृद्ध किया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान और भिलाई चैप्टर के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। भिलाई चैप्टर के सभी सदस्यों ने उनके बेटे आदित्य और शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है।

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर बनवाएं मात्र 3 दिन में
5 साल पुरानी ITR फाइल बनवाएं मात्र 5000/- में (व्हाट्सएप पर बनवाएं)
www.onlytds.com
GST-Return
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
TDS रिफंड
CMA DATA
MSME रजिस्ट्रेशन
Food लाइसेंस
संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544

पक्की नाली निर्माण से जुंगेरा के ग्रामीणों को मिलेगी जलजमाव से मुक्ति

- **विकसित भारत जी राम जी**

बालोद। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी के तहत ग्राम पंचायत जुंगेरा की वर्षों से चली आ रही जलजमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव में पक्की नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे बरसात में ग्रामीणों को जलभराव और गंदगी से मुक्ति मिल सकेगी।

ग्राम पंचायत जुंगेरा की सरपंच नीलम कोठारी ने पक्की नाली निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि इस पक्की नाली के निर्माण के लिए पंचायत द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पहले गांव में कच्ची नाली होने के कारण बरसात के दिनों में पानी का बहाव गलियों और लोगों के घरों तक पहुंच जाता था। इससे न केवल ग्रामीणों का रहन-सहन प्रभावित होता था, बल्कि उनके सामानों का भी भारी नुकसान होता था। ग्रामीण इस समस्या से बेहद दुखी और परेशान थे। उन्होंने कहा कि आज वर्षों की यह कोशिश रंग लाई है और इस पक्की नाली के निर्माण से अब ग्रामीणों का जीवन सुगम और शांतिपूर्ण हो सकेगा।

सरपंच श्रीमती नीलम कोठारी ने विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के सही संचालन और सहयोग के कारण ही आज गांव के धरातल पर ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। नाली निर्माण का कार्य शुरू होने से स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह है।

नशे में बच्चों से भरी स्कूल बस-वैन चला रहे थे चालक, दो दिन में दो पर कार्रवाई

- **यातायात पुलिस का बड़ा अभियान, वाहन जब्त**

भिलाई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है। यातायात पुलिस के विशेष अभियान के दौरान महज दो दिनों में दो स्कूल वाहन चालक शराब के नशे में बस और वैन चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत न्यायालय में पेश किया है। वहीं चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से स्कूल बसों और वैन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत 10 जुलाई को निरीक्षक जे.आर. कुर्रे की टीम ने कुम्हारी स्थित श्री स्कूल के बस चालक को 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल के स्तर के साथ वाहन चलाते हुए पकड़ा। वहीं सोमवार 13 जुलाई को श्री राम स्कूल की वैन का चालक 70 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल के प्रभाव में वाहन चलाते मिला। अभियान के दौरान एक अन्य स्कूल वाहन चालक भी नशे की हालत में पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई।

स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब

यातायात पुलिस ने संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है।

बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं : एडिशनल एसपी

यातायात की एडिशनल एसपी रिचा मिश्रा ने सभी स्कूल संचालकों और प्रबंधनों से अपील की है कि वे अपने वाहन चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में नशे की हालत में चालक को बच्चों के परिवहन की जिम्मेदारी न सौंपी जाए। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जरहागांव

// उद्घोषणा //

रा.प्र.क्रं. .... /ब-121/2025-26

ग्राम कोना प.ह.नं. 04

एतद् द्वारा समस्त ग्रामवासी ग्राम कोना वालो को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/कु. जुलाराम साहू पिता/पति स्व. प्यारेलाल जाति तेली निवासी ग्राम कोना तहसील जरहागांव, जिला मुंगेली छ.ग. द्वारा अपने पिता स्व. प्यारेलाल के मृत्यु दिनांक 10/07/1987 को ग्राम पंचायत कोना में दर्ज करने हेतु आदेश जारी करने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, अतः इस संबंध में जिस किसी को कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे दिनांक 30/07/2026 को प्रातः 11 बजे तक मेरे न्यायालय तहसील जरहागांव में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा को अधीन जारी किया गया।

सील

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
जरहागांव

//शपथ पत्र//

मैं नेहा कुर्रे (Neha Kurrey) उम्र 26 वर्ष पति सत्येन्द्र कुमार जाति सतनामी निवासी ग्राम बगबुडा पो. आ. भैसमा तहसील व जिला कोरबा छ.ग. का स्थाई निवासी हूँ, जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक करती हूँ- आधार क्रमांक 3093 5904 0047

यह कि मैं उक्त पते का स्थाई निवासी हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी नेहा कुर्रे (Neha Kurrey) दर्ज था जो कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम है। यह कि मेरी विवाह दिनांक- 01/05/2023 में श्री सत्येन्द्र कुमार पिता श्री विजय राम टांडे निवासी ग्राम बगबुडा पो. आ. भैसमा वाले के साथ शादी हो चुकी है। तदानुसार मैं अपना नाम श्रीमती नेहा टांडे (Neha Tande) पति श्री सत्येन्द्र कुमार लिखती हूँ। यह कि अब मैं विवाहित महिला हूँ। चुंकि विवाह के उपरांत श्रीमती नेहा टांडे (Neha Tande) पति श्री सत्येन्द्र कुमार अंकित कराना चाहती हूँ। यह कि मैं यह शपथ पत्र कु. से श्रीमती बनने हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कि मैंने किसी भी बातों एंव तथ्यों को नही छिपायी है।

शपथकर्ता
नेहा कुर्रे (Neha Kurrey)

बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर छत्तीसगढ़

संपादकीय

छत्तीसगढ़ राज्य जब वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था, तब यह केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि एक नए विकास मॉडल की शुरुआत थी। छोटे राज्यों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तर्क यही था कि छोटे राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर समझते हैं और विकास की गति तेज होती है। आज छत्तीसगढ़ उस तर्क की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने खड़ा है।

राज्य निर्माण के समय स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बहुत सीमित थी। पूरे प्रदेश का भार मुख्यतः रायपुर के एकमात्र बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज पर था। बस्तर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, दंतेवाड़ा या कबीरधाम जैसे दूरस्थ जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। यह केवल इलाज की समस्या नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी भी थी। पिछले पच्चीस वर्षों में इस तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। रायपुर में एम्स की स्थापना हुई, बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी संस्थानों का विकास हुआ।

सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ। नर्सिंग और डेंटल कॉलेजों की संख्या बढ़ी तथा जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें लगभग 2,300 से अधिक एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

अब राज्य सरकार ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर (कुनकुरी), जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन कॉलेजों को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से आवश्यक स्वीकृतियों और मानकों की चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करना आवश्यक है।

केवल मेडिकल कॉलेज खोल देना स्वास्थ्य क्रांति नहीं कहलाता। असली चुनौती उन कॉलेजों में योग्य प्रोफेसरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रदेश के अनेक जिला अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। कई डॉक्टर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय तक सेवा देने से बचते हैं। सरकार लगातार संविदा नियुक्तियां निकालती है, लेकिन पद अपेक्षित संख्या में नहीं भर पाते। यही कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि मानव संसाधन निर्माण है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार किए बिना स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस चुनौती को और कठिन बनाती हैं। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और बड़ी आबादी दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों में निवास करती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किसी भी सरकार के लिए कठिन कार्य रहा है। इसके बावजूद पिछले वर्षों में सड़क संपर्क, एंबुलेंस नेटवर्क, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास तेज हुआ है।

दरअसल, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च केवल खर्च नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश होता है। स्वस्थ नागरिक ही बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है, बेहतर रोजगार पैदा करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देता है। यदि किसी परिवार की आधी आय इलाज में चली जाए तो विकास के सारे दावे खोखले हो जाते हैं।

छत्तीसगढ़ ने उद्योग, कृषि, सड़क, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय है कि स्वास्थ्य को भी विकास की केंद्रीय धुरी बनाया जाए। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, मेडिकल रिसर्च, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल हेल्थ और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छोटे राज्य बनने का उद्देश्य केवल नया सचिवालय बनाना नहीं था, बल्कि आम आदमी तक बेहतर शासन पहुंचाना था। यदि दंतेवाड़ा का मरीज इलाज के लिए रायपुर न आए, बल्कि उसे अपने जिले में ही विशेषज्ञ उपचार मिल जाए; यदि जशपुर की बेटी डॉक्टर बनकर अपने जिले में सेवा दे। यदि बस्तर का आदिवासी आधुनिक चिकित्सा और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा दोनों प्राप्त कर सक, तभी राज्य निर्माण का सपना पूर्ण माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ ने विकास की लंबी यात्रा तय की है। अब अगला पड़ाव स्पष्ट होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर छत्तीसगढ़, क्योंकि किसी भी विकसित राज्य की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि स्वस्थ नागरिकों से होती है।

मानसून सत्र : सवालों की बारिश, जवाबों की परीक्षा

सुभाष मिश्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है, जब राज्य की राजनीति कई महत्वपूर्ण मुद्दों के मोड़ पर खड़ी है। एक ओर सरकार अपनी विकास योजनाओं, सुशासन और उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने को तैयार है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसलों, प्रशासनिक कार्यशैली और विभिन्न विवादों को लेकर उसे कठघरे में खड़ा करने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में यह सत्र केवल विधायी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा है। सत्र की शुरुआत ही राजनीतिक गर्मी के साथ हुई। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा पहले ही दिन सदन में गूंजा। यह मामला केवल किसी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा है। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि सरकार ने तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हर गंभीर प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाए। लेकिन बहस का उद्देश्य केवल राजनीतिक शोर नहीं, बल्कि समाधान होना चाहिए। सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंत्रियों और विधायकों की बैठक कर विभागवार तैयारी कराने का निर्णय स्वागतयोग्य है। विधानसभा में दिया गया हर उत्तर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। इसलिए तथ्यों के साथ जवाब देना केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व भी है। यदि मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित होते हैं, तो इससे सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है।

उधर कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। नकटी क्षेत्र में विधायक आवास निर्माण के लिए हटाए गए अतिक्रमण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शिक्षा व्यवस्था, किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर विपक्ष आक्रामक रहेगा। विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनहित के प्रश्नों को मजबूती से उठाना है। यदि उसके सवाल तथ्यपरक होंगे, तो सरकार को भी गंभीरता से जवाब देना होगा।

सरकार इस सत्र में बस्तर को अपनी उपलब्धियों के प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, सड़क, शिक्षा और विकास कार्यों में तेजी तथा मुख्यमंत्री के 'संवाद से समाधान' अभियान के परिणाम निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेंगे। यदि इन पहलों से वास्तव में आम लोगों का जीवन बदला है, तो यह सरकार की उपलब्धि है। लेकिन इन दावों की वास्तविकता की पड़ताल करना विपक्ष का भी दायित्व है।

लोकतंत्र में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सैकड़ों प्रश्नों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन तक पहुंचाते हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, रोजगार और अधूरी परियोजनाओं जैसे विषय केवल आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन से जुड़े प्रश्न हैं। सरकार यदि ईमानदारी से उत्तर देती है और विपक्ष तथ्यपरक ढंग से सवाल उठाता है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है।

चिंता की बात तब होती है, जब सदन का बहुमूल्य समय हंगामे और नारेबाजी में नष्ट हो जाता है। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन विरोध का उद्देश्य चर्चा को रोकना नहीं, बल्कि चर्चा को मजबूर करना होना चाहिए। इसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल बहुमत के आधार पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि विपक्ष के तर्कों को सुनना और उचित सुझावों को स्वीकार करना भी है।

आज जनता पहले से कहीं अधिक जागरूक है। विधानसभा की कार्यवाही अब केवल सदन की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के कारण हर प्रश्न, हर उत्तर और हर व्यवहार जनता के सामने होता है। लोग अब यह भी देखते हैं कि किस विधायक ने अपने क्षेत्र की आवाज उठाई, किस मंत्री ने तथ्यात्मक उत्तर दिया और किसने केवल राजनीतिक प्रदर्शन किया।

यह मानसून सत्र सरकार के लिए अपनी नीतियों और उपलब्धियों की परीक्षा है, तो विपक्ष के लिए अपनी विश्वसनीयता साबित करने का अवसर भी। यदि सरकार पारदर्शिता के साथ जवाब देती है और विपक्ष जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछता है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यदि पूरा सत्र केवल आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे में बीत गया, तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा।

विधानसभा किसी सरकार या विपक्ष की नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की संस्था है। वहां उठने वाला हर प्रश्न जनता की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस मानसून सत्र से यही अपेक्षा है कि राजनीतिक तापमान चाहे जितना ऊंचा रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा, तथ्यपरक बहस और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहें। आखिर लोकतंत्र की असली ताकत शोर में नहीं, जवाबदेही में होती है।

व्यंग्य

जेबी कफन

सुदर्शन सोनी

'जेबी कफन' है। बीच में 'सी' सीकर इसे 'जेसीबी कफन' कृपया न समझें? कि कस्बे-कस्बे गाँव गाँव इस मशीन के कारण हताश परेशान मजदूरों ने इसे जलाकर सुर्पदे खाक कर दिया। मार्क्स के समय यदि इस मशीन का अविष्कार हो गया होता तो इसका हर जगह यही हश्र होता! नहीं मैं तो एक कहानी सुना रहा हूँ, कफन बेचकर रातोंरात अरबपति बनने वाले एक गंगू नाम के व्यापारी की। यह एक छोटा व्यापारी था, छोटे-मोटे काम करके अपना पेट पालता था और मन ही मन सालता रहता था कि उसके अच्छे दिन आखिर कब आएँगे? वह क्यों नहीं, कार व इक बंगला न्यारा का मालिक हो, हवाई जहाज में विदेश की सैर करे! लेकिन उसके दिन नहीं फिरते थे। अच्छे दिनों के आने की उम्मीद तो वह कई सालों से बाँधे हुए था।

यह गंगू नाम का व्यापारी अपनी दुकान में खाली समय में किताबें, अखबार पढ़ता रहता था। आजकल अखबारों में पाजीटिव समाचार भी आने लगे है! और इनमें ज्यादातर ऐसे रहते कि कैसे किसी गरीब अभावग्रस्त व्यक्ति ने नाम मात्र की पूँजी से शुरू अपने धंधे से करोड़ों अरबो की संपत्ति बना ली या कोई-कोई एप बना कर अरबपति बन गया था, आदि। खाकपति से अरबपति बनने की कहानियाँ पढ़-पढ़कर उसके मन में भी ऐसे ही किसी एक आइडिया के बलबूते अपनी किस्मत चमकाने की इच्छा बलवती होने लगी। लेकिन कुछ खास क्रेक हो नहीं पा रहा था। सोते-जागते, वह यही सोचता कि किसी दिन उसके भी दिन बदलेंगे? और शायद वह अभी तक अड़ी-घड़ी जल्दी ही आने वाली थी!

अवसर तो किसी को यदि कफन ओढ़ाया जा रहा हो तो भी मौजूद रहता है नहीं तो 'जलती चिता में रोटी सेंकने' की कहावत कहाँ से प्रचलन में आई होती। उसके पड़ोस में रहने वाले लालाराम सेठ के प्राण पखेरू दिल के दौरे से पचास की पकी उम्र में ही उड़ गए। बेशुमार दौलत थी उसके पास, कहते हैं कि रोज रात नोट गिनते ही उसे सुबह के चार बज जाते थे! गंगू ने लालाराम से कई बार उधार लिया था। वैसे अब वह खुश था कि लालाराम गयाराम हो गया है तो उससे तकाजा करने कोई नहीं आएगा, लेकिन दूसरे ही पल सोचता कि नहीं किसी का पैसा खाना हराम है! यह सोचते-सोचते वह इस सेठ के द्वारे आ पहुँचा, आखिर वह इस सूदखोर का देनदार तो था ही। सेठ को कफन ओढ़ाया जा रहा था। सेठानी पछाड़ें ले लेकर रो रही थी। और गंगू को इसी समय एक आइडिया क्लिक कर गया कि इतनी बेशुमार दौलत का मालिक साथ में कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है! वैसे किसी की शव यात्रा में शामिल होने पर सबसे पहले तो गीता की पंक्तियाँ याद आती है कि तू क्या लाया था, जो लिया यहीं से लिया, क्या ले जा रहा है कुछ नहीं आदि। कारण पीछे केवल एक ही है कि कोई भी कफन जेबयुक्त नहीं होता! नहीं तो कहो वह सब साथ में इस आस में ले जाता कि परलोक में भी ऐशो-आराम में कोई कमी न होने पाए? और शायद इसी कारण मिस्र में राजा महाराजाओं की ममी के साथ उनके दास-दासियाँ, धन-दौलत, भी दफना दिए जाते थे। गंगू लालाराम की शव यात्रा के बाद घर आकर अपने इस धाँसू आइडिया को अमलीजामा पहनाने में लग गया। उसने चार दिन बाद ही अपनी किराने की दुकान बंद कर नए मिले आइडिया से उत्साहित होकर एक कफन बेचने की दुकान शुरू कर दी। कफन की दुकान चल निकली इतनी कि अब उसके पास किताब व अखबार पढ़ने का भी समय नहीं था। उसके कफन में क्या खास बात थी? कफन तो बस एक सफेद कपड़े के टुकड़े के अलावा क्या है? उसने 'जेबी कफन' के नाम से अपने उत्पाद का पेटेंट करा लिया था। उसके पास ऐसे-ऐसे डिजाइन के कफन थे, कि मरने वाला या मरने जा रहा शख्स खुश हो जाए जेब देखकर!, दो जेब वाला, चार जेब वाला, खुफिया जेब वाला, आगे जेब वाला, पीछे जेब वाला। जिप के जेब वाला, बटन के जेब वाला, लंबी जेब वाला, छोटे जेब वाला साथ में बटुआ लटका हुआ वाला। उसकी दुकान में दिन भर तिल रखने को भी जगह नहीं रहती! एक कफन तो ऐसा था कि उसमें हर स्थान पर जेब ही जेब थे। अब वह लाखों कमा रहा था। उसके जेबी कफन पास के देशों में एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गए थे! वह कुछ ही दिनों में शहर का सबसे बड़ा 'कफन एक्सपोर्टर' बन गया था। आखिर जेबी कफन चलते क्यों नहीं देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही थी। लोगों में काले धन के कारण संचय की प्रवृत्ति नई ऊँचाई पर थी।

उसने अब जेबी के साथ ही 'डिजायनर कफन' का भी स्टार्ट अप शुरू कर दिया था। चूँकि लोग अब मौत की रस्मों को भी डिजायनर तरीके से पूरी करना चाहते थे! वह पाँच सालों में ही शहर का एक करोड़पति व्यापारी हो गया था। उसके 'जेबी कफन' की चहुँ ओर माँग थीं। लेकिन कभी-कभी उसके मन में एक विचार आता था कि उसे अपने अंतिम समय के लिए जेबी कफन रखना चाहिए कि नहीं। वह उहापोह में था, निर्णय नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब भी वह ऐसा सोचता, तो उसे गीता की वो पंक्तियाँ याद आ जातीं फिर वह सोचता कि भले ही वह सबके लिए जेबी कफन बनाता हो लेकिन खुद बिना जेब वाला ही ओढ़ेगा।

कविता संसार

भूख की मुस्कान

चन्द्रकांत खुंटे 'क्रांति'

फटे बोरे के बिछौने पर जब पसर जाता है
दिनभर का थका-हारा बचपन
तब शुरू होती है एक मूक कहानी
दिनभर की गर्द,कूड़े के ढेरों की बदबू
और नंगे पैरों के छाले सब ओझल हो जाते हैं
नींद की गहरी आगोश में।
अंधेरी, ठंडी झुग्गी में कोई तारा नहीं चमकता
पर अचानक...उस सोए हुए मासूम के होंठ
हलके से फड़कते हैं
एक अलौकिक शांत मुस्कान
चेहरे पर तैर जाती है।
वहाँ कोई परियों का देश नहीं होता
न ही चमचमाती गाड़ियाँ होती हैं
न महँगे खिलौने, न नए कपड़े
वहाँ होती है सिर्फ एक गरम
गोल रोटी जो तवे से अभी-अभी उतरी हो
जिसकी सोंधी महक
उसकी आत्मा को तृप्त कर देती है
तरसते पेट को जब नींद की चादर छुपाती है
तभी बेबस लबों पर
एक अधूरी आस मुस्कुराती है
यकीं मानिए उस मासूम हंसी का
सबब कुछ और नहीं
ख्वाबों के तवे पर बस एक रोटी सिक जाती है।

क्या न्यायपालिका पर घट रहा है जनविश्वास?

महेन्द्र तिवारी

आज के समय में न्यायपालिका केवल संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों के अंतिम विश्वास का केंद्र भी है। जब कार्यपालिका और विधायिका से किसी व्यक्ति को राहत नहीं मिलती, तब उसकी अंतिम उम्मीद न्यायालय से जुड़ती है। ऐसे में यदि सर्वोच्च न्यायालय के भीतर ही ऐसी घटना घटे जिसमें एक याचिकाकर्ता न्यायाधीशों को ÷ज्यूडिशियल सर्वेंट÷ कहकर संबोधित करे, स्वयं को ÷सॉवरेन÷ घोषित करे, न्यायालय को आदेश देने की भाषा बोले, कागज हवा में उछाल दे और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, तो यह केवल एक व्यक्ति का अनुचित व्यवहार नहीं रह जाता। यह घटना न्यायपालिका, समाज और लोकतंत्र के संबंधों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं पैरवी कर रहे प्रबल प्रताप द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बाद अदालत की कार्यवाही बाधित हुई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर ले जाकर स्थिति को सामान्य किया। यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन गई।

इस घटना को देखने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला यह कि यह पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। दूसरा यह कि यह उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो वर्षों से लंबित मामलों और न्याय मिलने में होने वाली देरी के कारण समाज के एक वर्ग में पनप रहा है। दोनों दृष्टिकोणों को समझे बिना इस घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है।

भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। अनेक मामलों में न्याय पाने में वर्षों नहीं बल्कि दशकों का समय लग जाता है। कई बार मुकदमे की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अंतिम निर्णय देखने के लिए जीवित भी नहीं रहता। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां अगली पीढ़ी मुकदमा लड़ती रहती है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से लोगों में निराशा पैदा करती है। प्रसिद्ध कहावत है कि विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करने के समान होता है। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो रहा, तब व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। यही कमजोर होता विश्वास कभी-कभी आक्रोश का रूप भी ले लेता है।

लेकिन क्या यह आक्रोश अदालत के भीतर अनुशासन तोड़ने का अधिकार दे देता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। न्यायिक निर्णयों की आलोचना भी की जा सकती है। पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है।

सिर्फ क्रिकेट नहीं, अब मैदान बड़ा चाहिए!

-प्रभात झा बिलासपुर

138वें नंबर से विश्व कप तक भारतीय फुटबाल का लंबा रास्ता

शाम ढलते ही मणिपुर के एक छोटे से गांव का धूल भरा मैदान अचानक जी उठता है। स्कूल की छुट्टी खत्म होते ही दर्जन भर बच्चे नंगे पांव गेंद के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मैदान के किनारे खड़े एक बुज़ुर्ग के मोबाइल पर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में चल रहे फीफा विश्व कप 2026 का कोई मैच लाइव चल रहा है। बच्चे बीच-बीच में खेल रोककर स्क्रीन पर झांकते हैं, फिर वापस मैदान में कूद पड़ते हैं—मानो हर पास, हर शॉट में वही सपना बुन रहे हों जो स्क्रीन पर दिख रहा है।

यह दृश्य भारत के फुटबॉल-भविष्य की सबसे सच्ची तस्वीर है। देश में करोड़ों बच्चे यही सपना रोज़ देखते हैं, पर हकीकत कुछ और कहती है। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 138वें स्थान पर खड़ा है—211 सदस्य देशों वाले इस खेल में एक ऐसी जगह, जो हमारी आबादी और जुनून, दोनों के हिसाब से बेमेल लगती है।

पर इस साल एक बदलाव उम्मीद जगाता है। विश्व कप 2026 में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है, जिससे एशियाई फुटबॉल परिसंघ का कोटा 4.5 सीधी जगहों से बढ़कर 8.5 हो गया है। मतलब अब एशिया की शीर्ष नौ टीमें सीधे विश्व कप तक पहुंच सकती हैं। यह दरवाज़ा पहले से बड़ा तो हुआ है, पर उसमें दाखिल होने के लिए भारत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए ÷विज़न 2047÷ नाम की योजना शुरू की है—लक्ष्य है, आज़ादी के सौवें वर्ष तक भारत को एशिया की शीर्ष चार फुटबॉल शक्तियों में शामिल करना। यह योजना कागज़ पर जितनी आकर्षक है, ज़मीन पर उतारना उतना ही कठिन भी।

दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास एक ऐसा इलाका पहले से मौजूद है, जिसे फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है—पूर्वोत्तर भारत। इंडियन सुपर लीग और राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले 40 प्रतिशत से अधिक खिलाड़ी इसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। मणिपुर, मिज़ोरम और असम के गांव-गांव में फुटबॉल केवल खेल नहीं, पारिवारिक स्वीकृति का हिस्सा है—यहां किसी बच्चे का फुटबॉलर बनना उतना ही सामान्य माना जाता है जितना डॉक्टर या इंजीनियर बनना। यही वह सबक है जो बाकी भारत को अभी सीखना बाकी है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती; उसके लिए बचपन से व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कोच, खेल विज्ञान और मज़बूत घरेलू लीग ढांचे की ज़रूरत होती है। इंडियन सुपर लीग ने बीते एक दशक में फुटबॉल को नया मंच दिया है, कई राज्यों ने अकादमियां भी खोली हैं—पर ये कोशिशें भारत की विशालता के सामने अब भी एक बूंद जैसी हैं।

भारतीय फुटबॉल का संघर्ष केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा। एआईएफएफ में नेतृत्व-विवाद, कानूनी अड़चनें और नीतिगत अस्थिरता ने कई अच्छी योजनाओं को अधूरा छोड़ा है। जिन देशों ने फुटबॉल में मुकाम हासिल किया—जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे उदाहरण देखें—वहां प्रशासनिक स्थिरता और दीर्घकालिक सोच पहली शर्त रही है। ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट में भी उतना ही मज़बूत है, फिर भी उसने फुटबॉल को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। असली सवाल संसाधनों का नहीं, प्राथमिकता के बंटवारे का है। क्रिकेट ने भारत को जो पहचान और गर्व दिया है, वह अमूल्य है। पर किसी एक खेल की चमक बाकी खेलों के अंधेरे का कारण नहीं बननी चाहिए। असली खेल संस्कृति वहां बनती है जहां क्रिकेट के साथ फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती और एथलेटिक्स को भी बराबर की जगह और सम्मान मिले।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खेल को पढ़ाई से अलग खाने में रखने के बजाय शिक्षा का ही हिस्सा माना है। अगर स्कूलों में फुटबॉल को साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता तक सीमित न रखकर नियमित प्रशिक्षण, फिटनेस मूल्यांकन और स्थानीय लीग से जोड़ा जाए, तो मणिपुर के उस धूल भरे मैदान जैसे हज़ारों मैदान पूरे देश में खिलाड़ियों की खान बन सकते हैं।

उस शाम, मैदान के किनारे बैठे बुज़ुर्ग के मोबाइल की स्क्रीन आखिरकार बंद हो गई, पर मैदान में गेंद तब भी घूम रही थी। शायद यही भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है—सपना कभी नहीं थकता, भले ही रास्ता लंबा हो। ज़रूरत बस इतनी है कि यह जुनून किसी योजना, किसी कोच, किसी मैदान तक पहुंच पाए। जिस दिन देश के हर गांव का धूल भरा मैदान किसी अकादमी से जुड़ जाएगा, भारत विश्व कप का दर्शक नहीं, दावेदार बनकर मैदान में उतरेगा।

भारत को खेल-महाशक्ति बनने के लिए किसी एक चैंपियन की नहीं, हज़ारों मणिपुरी गांवों जैसे मैदानों की ज़रूरत है, जहां सपना पहले से मौजूद है—बस रास्ता चाहिए। यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी जीत होगी।

नवगई हत्याकांड

जांच के लिए कोरिया पहुंची सीबीआई

- 6 सदस्यीय दल आज से शुरू करेगी पड़ताल

कोरिया। बहुचर्चित नवगई हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथों में पहुंच चुकी है। मामले की जांच के लिए सीबीआई का छह सदस्यीय दल रविवार को कोरिया जिले पहुंच गया। टीम चरचा स्थित पंचवटी अतिथि गृह (एसईसीएल, चरचा आर.ओ.) में ठहरी हुई है और सोमवार से मामले की औपचारिक जांच शुरू करेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही अब तक की पुलिस जांच, केस डायरी, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान मामले से जुड़े गवाहों, संबंधित अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, जांच को वैज्ञानिक आधार देने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी जल्द कोरिया पहुंच सकती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल और उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, जिससे मामले के प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित हो सके। सीबीआई जांच शुरू होने की खबर के बाद पूरे जिले में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पीड़ित परिवार सहित आम नागरिकों को उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की निष्पक्ष जांच से घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल सीबीआई की ओर से जांच की रणनीति या प्रगति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, दस्तावेजों की गहन समीक्षा तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

जमीन हथियाने का षडयंत्र, विधवा महिला को डरा-धमकाकर वसूले पैसे

सूरजपुर। जिले के ग्राम पंचायत खड़गवां से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक असहाय और विधवा महिला को फर्जी दस्तावेजों और डरा-धमकाकर जमीन हथियाने के नाम पर अवैध वसूली का शिकार बनाया गया है। पीड़ित महिला ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता रस्मेन राजवाड़े ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से उसकी पैतृक भूमि को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसे डरा-धमकाकर गलत तरीके से जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और एग्रीमेंट के नाम पर जबरन वसूली की गई है।

पुलिस से भी की गई थी शिकायत

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय चौकी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।

न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी

दबंगों के इस कृत्य से आहत और लाचार पीड़िता ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उसे समय रहते न्याय नहीं मिला और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी।

अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की सख्त कार्यवाही

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में जिला सूरजपुर के खनिज अमला, राजस्व अमला एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध सतत जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान पत्थर, गिट्टी, मुरुम, मिट्टी, ईट, रेत आदि खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर संलग्न मशीनरी एवं वाहनों को नियमानुसार जब्त कर अवैध उत्खनन/परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है तथा अर्थदण्ड की वसूली भी की जा रही है। इसी क्रम में माह जुलाई में विभागीय अमला एवं जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2026 को भैयाथान के गंगोटी क्षेत्र से कुल 04 वाहनों (हाईवा) में कुल 56 घन मीटर अवैध रेत का परिवहन करते पाया गया।

नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने संभाला कार्यभार

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) के अधिकारी हरीश राठौर ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बैकुण्ठपुर पहुंचकर जिले के 23वें पुलिस अधीक्षक के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया।

पदभार ग्रहण करने के बाद राठौर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग व्यवस्था तथा विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जिले की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझा और आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। हरीश राठौर ने कार्यभार संभालने के साथ ही जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराधों पर नियंत्रण तथा जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिलेवासियों को भी नए पुलिस अधीक्षक से पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी पुलिस व्यवस्था की अपेक्षा है।

कलेक्टर ने ली कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक

सूरजपुर। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जमीन संबंधी विवादों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। साथ ही विभिन्न समाज एवं संप्रदायों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की रैली, धरना-प्रदर्शन एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

बंदियों ने सीखा अगरबत्ती, साबुन और हैंडवॉश निर्माण

- जिला जेल सूरजपुर में आरसेटी का कौशल प्रशिक्षण संपन्न

सूरजपुर। जिला जेल सूरजपुर में बंदियों के पुनर्वास एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), सूरजपुर द्वारा आयोजित 13 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 35 बंदियों ने भाग लेकर अगरबत्ती, साबुन एवं हैंडवॉश निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

जिला जेल अधीक्षक विक्रम गुप्ता के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आयोजित यह प्रशिक्षण 2 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक संचालित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कम लागत में स्वरोजगार स्थापित करने, उत्पाद निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, विपणन तथा बैंकिंग संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। आरसेटी सूरजपुर के निदेशक अशोक कुमार राणा, फैकल्टी परमानंद एवं मयंक तिवारी, तथा प्रशिक्षक श्रीमती भगवंती ने प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस सभी 35 प्रतिभागियों का लिखित एवं प्रायोगिक मूल्यांकन ईडीपी एवं डोमेन असेसर द्वारा किया गया। इस अवसर पर आरसेटी के निदेशक अशोक कुमार राणा, फैकल्टी मयंक तिवारी एवं डीएसटी श्रीमती भगवंती उपस्थित रहे।

जेल अधीक्षक विक्रम गुप्ता ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ उन्हें रिहाई के बाद आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस पहल के लिए आरसेटी की पूरी टीम की सराहना की।

आरसेटी के निदेशक अशोक कुमार राणा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि रिहाई के बाद बैंक लिंकेज, ऋण सुविधा एवं दो वर्ष तक हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराकर बंदियों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग देना भी है। उन्होंने बताया कि अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

कलेक्टर जनदर्शन में 48 शिकायतें प्राप्त

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने आज आयोजित साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें सुनीं। जनदर्शन में कुल 48 शिकायत एवं आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण शामिल रहे। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सूरजपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान को मिली नई दिशा

कलेक्टर रेना जमील एवं जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले के नेतृत्व में अधिकारी बने निक्षय मित्र

सूरजपुर। स्वास्थ्य विभाग ने सूरजपुर जिले में ''टीबी मुक्त भारत - गांव गांव, शहर शहर'' 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित क्षय रोगियों के उपचार एवं पोषण आहार उपलब्ध कराने के साथ ही नये निक्षय मित्र जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया है। इस पहल के तहत सामाजिक स्तर पर लोग क्षय रोगियों को गोद लेंगे और अगले छह माह से अपनी इच्छानुसार एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक उनके पोषण का ध्यान रखेंगे।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र अभियान को जिले की कलेक्टर रेना जमील एवं जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले के नेतृत्व में नई दिशा दी गई। समय सीमा की बैठक में जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा कुल 20 टीबी मरीजों को अभियान के अंतर्गत गोद लेकर उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान की गई। इस

अवसर पर कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि जिले में टीबी रोगियों को दानदाताओं की उपस्थिति में पोषण आहार किट का वितरण किया जा रहा है, जो आम जनों के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ने और टीबी मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान देने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान से जिले में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, मरीजों के प्रति भेदभाव समाप्त होगा तथा सूरजपुर को टीबी मुक्त जिला बनाने में सहायता मिलेगी।

जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं पोषण आहार किट के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर एवं सीईओ की अपील पर महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल, खाद्य अधिकारी संदीप भगत, वन विभाग के एसडीओ अशोक तिवारी, माइनिंग ऑफिसर भूषण पटेल, सहायक संचालक उद्यान जयपाल सिंह मारवी, डीएमसी समग्र शिक्षा मनोज साहू, डॉ. नृपेन्द्र सिंह, आर.ई.एस. से संजय कुमार गोढ़, ट्रेजरी ऑफिसर प्रेमशंकर तिवारी, उप संचालक पंचायत विक्रम बहादुर, ईडीएम सुमित सिंह, डीआईओ एनआईसी रोहन सिंह, जनपद ओढ़गी के सीईओ नीलेश सोनी, जनपद भैयाथान के सीईओ विनय गुप्ता, जनपद प्रतापपुर के सीईओ अनिल तिवारी एवं जीएम डीआईसी फिलिप तिग्गा ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को उनके उपचार के दौरान पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक कुल छह माह अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। ये सभी निक्षय मित्र जिले के चयनित टीबी मरीजों को उच्च प्रोटीनयुक्त पोषण आहार किट प्रतिमाह उपलब्ध कराएंगे।

कलेक्टर ने नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

- स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में संचालित गुटखा एवं सिगरेट बिक्री केंद्र हटाने के निर्देश

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, आबकारी अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से एनकॉर्ड के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई।

बैठक में जिले में युवाओं का नशीले पदार्थों के उपभोग में संलिप्तता पर कलेक्टर ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार एवं इसके प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग निर्धारित जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। कलेक्टर ने स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर के दायरे में संचालित गुटखा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले केंद्रों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने, निर्देश दिए।बैठक में नशामुक्ति के लिए जनचौपाल, जनजागरूकता अभियान, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम तथा आमजन की सहभागिता से नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान संचालित करने पर भी जोर दिया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
निविदा सूचना
निविदा सूचना सं.: म.सा.प्र./ ई.एम.डी/ द.पू.म.रे. रायपुर निविदा सं. 48265043. कार्य का नाम: सप्लाई एंड इन्स्टालेशन ऑफ डबल साइड स्विंग डोर्स इन सेट्स कोन्फोर्मिंग टु ICF स्पेसिफिकेशन नं. ICF/ MD/ SPECN-268- (1) डबल साइड स्विंग डोर एसम्बली (Alu Door with S.S. Fixing Frame) टु ICF ड्राइंग नं. ICF/ SK3-5-6-014 Col-I Alt-h/ Nil, मात्रा: 1 नग/सेट. (2) डबल साइड स्विंग डोर एसम्बली (Alu Door with S.S. Fixing Frame) टु ICF ड्राइंग नं. ICF/ SK3-5-6-014 Col-II Alt-h/ Nil, मात्रा: 1 नग/ सेट. मटेरियल स्पेसिफिकेशन एज पर ड्राइंग। मात्रा: 100 सेट. समाप्ति तिथि: 05.08.2026. 10.30 AM (1) निविदा दस्तावेज वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है और वहीं डॉउनलोड भी किया जा सकता है। (2) सभी बोलीदाताओं/ निविदाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी का अनुपालन कर रहे है और जीएसटी कानून के अनुसार कर संरचना/दर उद्धृत करते है। (3) निविदा अनुबंध से संबंधित अन्य पुछताछ के लिए मंडल सामग्री प्रबंधक कार्यालय/ ई.एम.डी/ डीजल लोको शेड, पोस्ट-पंडरी, रायपुर-492004 (C.G.) मो.नं. 09725440905 से सम्पर्क करें।
मंडल सामग्री प्रबंधक
ई.एम.डी. दपूम रेलवे रायपुर
PR/R/DMM/EMD/D360/130
South East Central Railway @secrail

एचपीवी टीकाकरण, माय भारत पंजीयन के निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक संपन्न

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिले में 13 से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह के सफल आयोजन हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि एचपीवी संक्रमण महिलाओं में सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर का प्रमुख कारण है तथा समय पर लगाया गया टीका इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा की प्रभावी ढाल है।

कलेक्टर ने एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह

अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, अनुदान प्राप्त विद्यालयों, आश्रम-छात्रावासों, मदरसों तथा विद्यालय से बाहर की पात्र बालिकाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, जिन क्षेत्रों में उपलब्धि अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष फोकस करने की बात कही। उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से तय समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने को कहा। इसके साथ ही प्रत्येक टीकाकरण सत्र की जानकारी यू-विन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये।

इसी क्रम में बैठक में माय भारत (मेरा युवा भारत) के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार एवं जिला समन्वय समिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 25 हजार युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़ने के लक्ष्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, कौशल विकास संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र तथा अन्य युवा संगठनों के समन्वय से विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक पात्र युवाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि माय भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच है, जिसके माध्यम से उन्हें स्वयंसेवा, नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास, कौशल संवर्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं आयोजनों में भागीदारी के अवसर प्राप्त होते हैं। जिला युवा अधिकारी ने बताया कि सभी पात्र युवा वेबसाइट पर निःशुल्क ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। बैठक में कलेक्टर ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अपील की कि वे 14 से 15 वर्ष की प्रत्येक पात्र बालिका को निकटतम सत्र में निःशुल्क एचपीवी टीका अवश्य लगवाएं तथा पात्र युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़कर इस जनहितकारी अभियानों को सफल बनाने में सहयोग करें।

जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र पर गबन के आरोप,कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

- गबन के आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित

सूरजपुर। बीते दिनों जनपद निधि से कराए गए विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच जिला पंचायत सदस्य एवं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने सोमवार को कलेक्टर सूरजपुर को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्हें प्रशासन की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है तथा वे हर स्तर की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।अपने आवेदन में नरेंद्र यादव ने कहा है कि ग्राम गणेशपुर निवासी राजकुमार दुबे द्वारा वर्ष 2024-25

में जनपद निधि से ग्राम कमलपुर में कराए गए विकास कार्यों को लेकर लगाए गए आरोप उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करने और बढ़ते जनसमर्थन को प्रभावित करने की मंशा से लगाए गए हैं। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में कराए गए सभी विकास कार्य पूरी पारदर्शिता और शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न हुए हैं तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या शासकीय राशि के गबन का प्रश्न ही नहीं उठता।जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि संबंधित क्षेत्र में वास्तविक रूप से खनन कार्य हुए हैं, गबन का आरोप लगाकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे मामले का भौतिक सत्यापन कराया जाए तो वास्तविक स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी।उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच समिति गठित कर निर्धारित समय सीमा में सभी कार्यों का तकनीकी और भौतिक सत्यापन कराया जाए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तथा सच जनता के सामने आ जाएगा।जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि जनहित, प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है।

शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य

जनदर्शन के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण के निर्देश

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता में सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में श्रीमती त्रिपाठी ने विभागीय कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने वीबी जी रामजी के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक रोजगार स्वीकृत करने एवं पात्र हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से मैदानी भ्रमण कर कार्यों की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करें तथा कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की समीक्षा करते हुए बेहतर प्रबंधन एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को

निर्देशित करते हुए कहा कि पुनर्वास नीति-2025 के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही तक शासन की योजनाओं का लाभ सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि पुनर्वास नीति का उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को राहत प्रदान करना तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिजन, आत्मसमर्पित नक्सली, नक्सली हिंसा में घायल आम नागरिक तथा जिनकी संपत्ति को क्षति पहुंची है, ऐसे प्रभावित परिवारों को पात्रता के अनुसार शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए रोजगार से जोड़ने के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, मध्यान्ह भोजन में हरी सब्जी उपलब्ध कराने तथा सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। कलेक्टर ने बैग एवं गणवेश वितरण की जानकारी लेते हुए सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेश का वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत वितरण की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने जाति एवं आय प्रमाण-पत्र शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूडीआईडी की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में स्कूल जतन योजना के अंतर्गत नवीन शौचालय निर्माण, वर्ष 2024-25 के पूर्ण कार्यों का मैदानी सत्यापन तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही वर्ष 2025-26 के स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने को कहा।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने खाद एवं बीज की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों तथा विकासखंडवार एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल तथा कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा सहित लंबित राजस्व प्रकरणों तथा लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन, जिला शाखा राजनांदगांव ने प्रदेश के पेंशनर्स की लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम अनुशंसा पत्र भेजने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव के निर्देश पर चलाया गया। जिला अध्यक्ष आरके महानदिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉ. रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे तथा डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशनर्स की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैरी जोसेफ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

ज्ञापन में नियमित कर्मचारियों के समान लंबित महंगाई राहत का भुगतान, पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, 80 वर्ष के बजाय 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप छठवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में पेंशनर्स को शामिल करने, राज्य पेंशनर्स कल्याण मंडल का पुनर्गठन तथा सभी जिलों में सियान सदन (पेंशनर्स भवन) के निर्माण की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इन मांगों के समर्थन में राज्य शासन को अनुशंसा पत्र भेजकर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

इस अवसर पर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य बृजलाल कडबे, भारतलाल देवांगन, रूपचंद साहू, अर्जुन देवांगन, सुपेत, जोगीराव खोब्रागढ़े तथा एसोसिएशन के संरक्षक एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष व जिला सचिव आनंदकुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जल संरक्षण का संकल्प वर्षा जल का अधिकतम संचयन

भू-जल संवर्धन की दिशा में जिलेभर में व्यापक पहल

बलरामपुर। जल ही जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी सोच को साकार करते हुए जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सभी विकासखंडों में जल संचयन एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण की दिशा में 5 प्रतिशत जल संरक्षण मॉडल के अंतर्गत व्यापक स्तर पर कार्य किए गया है। जिले में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को अपने खेतों में मॉडल जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशासन और ग्रामीणों की सहभागिता से बड़ी संख्या में किसानों ने अपने खेतों में जल संरक्षण के मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे वर्षा जल का अधिकतम संचयन

सुनिश्चित हो रहा है।

जिले के सभी विकासखंडों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन के विभिन्न कार्य किया गया है। खेतों, नालों, सार्वजनिक स्थलों तथा जल निकासी वाले क्षेत्रों में ऐसी संरचनाएं विकसित की गई हैं, जिनसे वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ जाने के बजाय भूमि के भीतर समाहित हो रहा है। इससे भू-जल स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और प्राकृतिक जल स्त्रोतों को भी नया जीवन मिल रहा है।

अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, मैदानी अमले और जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराया। ग्रामीणों को बताया गया कि यदि प्रत्येक खेत में वर्षा जल को रोकने और जमीन में उतारने की व्यवस्था की जाए, तो भविष्य में सिंचाई और पेयजल की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। किसानों ने भी इस पहल को उत्साहपूर्वक अपनाते हुए अपने खेतों में मॉडल स्ट्रक्चर का निर्माण कराया। 5 प्रतिशत मॉडल का उद्देश्य केवल वर्षा जल का संग्रह करना नहीं, बल्कि जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाना है। इस पहल से वर्षा जल का संचयन बढ़ रहा है।

23 पेटी अवैध शराब विभाग ने जब्त की

जनधारा समाचार

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देशानुसार प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में 12 जुलाई 2026 को सूचना के आधार पर आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी रमा शंकर सिंह (उर्फ) बाबा स्थान बैकुण्ठ धाम के पास फौजी नगर थाना जामुल जिला-दुर्ग द्वारा बिना नम्बर प्लेट स्विफ्ट डिजायर से रॉयल गोवा व्हिस्की (गोवा प्रान्त की मदिरा) 23 पेटी पाव कुल मात्रा 198.720 बल्क लीटर मदिरा को परिवहन करते पाये जाने पर उक्त मदिरा एवं वाहन को जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बिना परमिट के आरोपी के कब्जे से गोवा प्रान्त की विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया है। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है।

इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गायत्री विद्यापीठ ने लहराया परचम

राजनांदगांव। जिले की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था गायत्री विद्यापीठ, राजनांदगांव के विद्यार्थियों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं जिले का गौरव बढ़ाया। यह प्रतियोगिता कस्तूरबा महिला मंडल, राजनांदगांव में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता में गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 18 रजत एवं 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। विजेता खिलाड़ियों में जैमिनी साहू, योजित साहू, मोक्ष साहू, कबीर साहू, तोमन सोनकर, सचेतन चौगुले, मेहल राजगर, खुश चावड़ा, वार्या टेंडेकर, परिधी वैष्णव, जिज्ञांशु साहू, मोहन, वेद पटेल, प्रियंका चौबुले एवं ख्याति साहू शामिल रहे।

इस अवसर पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर सागर चितलांग्या ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि कराटे केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस और आत्मरक्षा की उत्कृष्ट कला है। हमारे विद्यार्थियों ने अपने समर्पण, कठिन परिश्रम और नियमित अभ्यास के बल पर यह सफलता अर्जित की है। मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गायत्री विद्यापीठ और राजनांदगांव का नाम गौरवान्वित करेंगे।

क्रीड़ा अधिकारी अखिलेश मिश्रा एवं कराते शिक्षक जयप्रकाश साहू, जयदीप सिन्हा एवं अन्नपूर्णा साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं नियमित प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

सीबीएसई प्राचार्य अंकित व्यास ने सभी विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों तथा प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि गायत्री विद्यापीठ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा के साथ खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन विद्यालय की पहचान बन चुका है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएँ दीं।

2 एकड़ शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त

छठ घाट एवं धार्मिक आयोजनों के लिए सुरक्षित हुआ

बलरामपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में तहसील बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पुत्सुरा में लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

उक्त भूमि का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा वर्षों से छठ पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों एवं अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है। सार्वजनिक महत्व को देखते हुए राजस्व विभाग द्वारा ग्राम के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में आवश्यक कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। भूमि अतिक्रमण से मुक्त होने के बाद अब यह स्थल पुनः धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित हो गया है, जिस ग्रामवासियों ने संतोष व्यक्त किया है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि, जल स्त्रोतों तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

कृषि इनपुट की उपलब्धता से समृद्ध हो रहे कृषक

समय पर यूरिया व उन्नत खाद मिलने से फसल चक्र हुआ सुदृढ़

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के आर्थिक संवर्धन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, खरीफ सीजन के दौरान कृषकों को आवश्यक कृषि आदान (कृषि इनपुट) सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धरातल पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन दुर्ग की सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विज्ञान के दृष्टिकोण से यूरिया और अन्य खाद फसलों की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि, क्लोरोफिल निर्माण और समुचित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, जो फसल की उत्पादकता व गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। दुर्ग विकासखंड के ग्राम जेवरा निवासी प्रगतिशील कृषक कमलेश कुमार साहू ने बताया कि उन्हें सिरसा स्थित

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता के अनुरूप दो चरणों में यूरिया खाद एवं उन्नत बीज अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो गए हैं। खेती-किसानी के इस संवेदनशील समय में कृषि आदानों की त्वरित उपलब्धता से खेतों में बुआई और पोषण प्रबंधन का कार्य बिना किसी मानसिक व आर्थिक तनाव के समय पर पूरा हो सका है। कृषक साहू ने अपने पिछले अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों को खादों के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे समय नष्ट होता था और फसल भी प्रभावित होती थी। किंतु इस वर्ष प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यूरिया और बीज बिना किसी परेशानी के सीधे किसानों तक सहजता से पहुंच रहे हैं। समयबद्ध तरीके से मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति होने से फसलों के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है, जिससे आगामी समय में बंपर पैदावार की ठोस उम्मीद जगी है। शासन की इस किसान-हितैषी नीति और पारदर्शी वितरण प्रणाली से अभिभूत होकर कृषक कमलेश कुमार साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन दुर्ग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खाद-बीज की निर्बाध उपलब्धता से जिले के कृषक समुदाय का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे पूर्ण उत्साह के साथ खरीफ सीजन की खेती में संलग्न हैं।

विश्व पेपर बैग दिवस पर विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

राजनांदगांव। शिक्षा एवं संस्कार के क्षेत्र में अग्रणी जिले की ख्याति प्राप्त संस्था गायत्री विद्यापीठ में विश्व पेपर बैग दिवस के अवसर पर कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक मुक्त भारत के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हे विद्यार्थियों ने अपने हाथों से निर्मित पेपर बैग आसपास के क्षेत्रों में घर-घर जाकर वितरित किए तथा नागरिकों को प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल पेपर बैग अपनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने अपने उत्साह, अनुशासन और जागरूकता से समाज को पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया।

रैली के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आकर्षक नारों के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से अवगत कराया तथा दैनिक जीवन में कागज के थैलों के उपयोग का आग्रह किया। बच्चों की मासूम अपील और उनके हाथों से बने पेपर बैग लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय नागरिकों ने भी इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण संरक्षण में

सक्रिय सहयोग का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्राथमिक विभाग की प्रमुख शिक्षिका श्रीमती वसुधा लड्डा के मार्गदर्शन में श्रीमती सीमा गायधने, श्रीमती गायत्री मिश्रा एवं सुश्री गरिमा यादव का विशेष योगदान रहा। शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर प्राचार्य अंकित व्यास ने अपने संदेश में कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है। आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक हैं। यदि वे अभी से पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर समाज को सही दिशा देंगे, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण प्राप्त होगा। प्लास्टिक का उपयोग

सर्वग्य राव शूटिंग अकादमी राजनांदगाव के खिलाड़ी राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेगा

राजनांदगांव। सर्वग्य राव शूटिंग एकेडमी राजनांदगाव के 14 खिलाड़ियों का दल छत्तीसगढ़ राज्य राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये रायपुर जायेगाण् इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के खिलाडी विभिन्न आयु वर्ग में भाग लेंगेण् इस प्रतियोगिता में 10, 25 और 50 मीटर एयर पिस्टल तथा 10, 25 और 50 मीटर एयर राइफल में सब युथ, युथ, जूनियर, सीनियरए, मास्टर्स, सीनियर मास्टर और सुपर मास्टर आयु वर्ग के खिलाडी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में सर्वज्ञ राव शूटिंग एकेड़मी राजनांदगांव के विवान भोजानी, हितांश बैद, शिवांश शर्मा, कालवा अथर्व राव, कालवा सर्वज्ञ राव, शुकुन मोटलानी, दर्शना भट्टाचारजी, गुरकिरत कौर, अंजनी, वैभवी थावरे, जान्हवी कुमारी सभी सब युथ में भुमिका साहु युथ में, कालवा राधा राव सिनियर में एवं कालवा राजेश्वर राव सिनियर मास्टर्स में भाग लेंगे।

टीम की कोच सुश्री ख्याति तालियान (एनआईएस डिप्लोमा कोच) होंगी।

दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन ने संभाला पदभार

नक्सल विरोधी अभियान, कानून-व्यवस्था और जन-केंद्रित पुलिसिंग को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

जनधारा समाचार

दंतेवाड़ा /बचेली। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन सिंह (भा.पु.से.) ने आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा का विधिवत पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दंतेवाड़ा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दंतेवाड़ा से पुलिस अधीक्षक, बलौदा बाजार के पद पर स्थानांतरित गौरव राय (भा.पु.से.) को स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनके सफल कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा नवीन दायित्व हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं।

पदभार ग्रहण करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित कर जिले की कानून-व्यवस्था, नक्सल विरोधी एवं पुनर्वास अभियान, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं तथा पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग सुनिश्चित करते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही अपराधों के

त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण, जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान तथा पुलिस-जन संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, विश्वास एवं सहयोग को सर्वोपरि रखते हुए प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना, अनुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता तथा पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। कार्यभार ग्रहण के अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके सफल, प्रभावी एवं जनोन्मुखी कार्यकाल की शुभकामनाएँ व्यक्त कीं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दंतेवाड़ा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दंतेवाड़ा से पुलिस अधीक्षक, बलौदा बाजार के पद पर स्थानांतरित गौरव राय (भा.पु.से.) को स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनके सफल कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा नवीन दायित्व हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं।

सेवा सेतु से आसान हुई प्रक्रिया, अजय को मिला मूल निवासी प्रमाण पत्र

दुर्ग। पाटन निवासी अजय चन्द्राकार को अपने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले उन्हें यह चिंता थी कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु पहल ने उनकी यह चिंता पूरी तरह दूर कर दी। अजय चन्द्राकार ने 14 मई 2026 को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 मई 2026 को उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र समय पर जारी कर दिया गया।

सेवा सेतु के माध्यम से उन्हें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिली, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और बिना किसी अनावश्यक परेशानी के प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। अब वे इस प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न शासकीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों में आसानी से कर पा रहे हैं। अपने अनुभव को साझा करते हुए अजय चन्द्राकार ने कहा, ष्सेवा सेतु के माध्यम से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही सरल और सुविधाजनक रहा।

विश्व जनसंख्या दिवस पर संगोष्ठी, पोस्टर एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित

दुर्ग। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संगोष्ठी, पोस्टर, भाषण एवं ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

निधन

सुरेश कराडे

भिलाई। सेक्टर 11, खुर्शीपार निवासी सुरेश कराडे पिता स्व. पांडुरंग कराडे का सोमवार, 13 जुलाई को निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार 14 जुलाई को प्रातः 11 बजे उनके निवास क्वार्टर नंबर वन ए, स्ट्रीट 22, जोन 1, सेक्टर 11, खुर्शीपार, भिलाई से निकलेगी। अंतिम संस्कार रामनगर मुक्तिधाम में किया जाएगा। वह चंद्रशेखर कराडे के बड़े भाई एवं शीतल कुमार कराडे के पिता थे।

उर्वरक बिक्री में अनियमितता पर प्रशासन सख्त

निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करने पर 1 दुकान नोटिस जारी

● 5 दुकानों पर विक्रय पर प्रतिबंध

बलरामपुर। किसानों को उर्वरकों की निर्धारित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में उर्वरक दुकानों की सतत निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग एवं प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर व बलरामपुर में जांच के दौरान कुल 5 दुकानों में खाद बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा 1 दुकान को नोटिस जारी किया गया। साथ ही एक दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंडरी स्थित सुरेन्द्र खाद भण्डार दुकान के संबंध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दुकान की जांच की गई। जिसमें जांच में पाया गया कि दुकान संचालक के द्वारा खाद बिक्रय में अनियमितता बरती जा रही थी। जिस पर संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार वाड्रफनगर में जायसवाल फर्टिलाइजर्स में प्राप्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय संबंधी शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बताया कि निर्धारित मूल्य 532 रुपये के स्थान पर 600 रुपये लिए जाने की बात कही। जांच के दौरान दुकान से संबंधित बिल जांच दल द्वारा परीक्षण के लिए संज्ञान में लिया गया। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता एवं दुकान संचालक, दोनों पक्षों के कथन दर्ज किए गए। प्रथम दृष्टया तथ्यों के परीक्षण के उपरांत कृषि विभाग द्वारा दुकान संचालक को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं विधिक सहायता की दी गई जानकारी

● जनपद पंचायत केशकाल में वृहद विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

कोंडागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के द्वारा जनपद पंचायत केशकाल में महिलाओं के लिए वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय, व थाना प्रभारी केशकाल विकास बघेल, प्रतिधारक अधिवक्ता केशव ठाकुर सहित अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

इस कार्यकम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तभी समाज में वास्तविक न्याय, समानता और सशक्तिकरण स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये हैं तथा उनके सम्मान, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए अनेक प्रभावी कानून बनाए गये गये हैं। इन कानूनों की जानकारी प्रत्येक महिला तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि वे अन्याय, शोषण एवं हिंसा के विरूद्ध निर्भिक होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। साथ ही महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों की जानकारी भी होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव अथवा अन्याय कि स्थिति में कानून उनके साथ खड़ा है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों, उत्तराधिकार के अधिकार, साइबर अपराधो से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विशेष दिव्यांगजन विद्यालय हाईटेक

स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा 9वीं की पढ़ाई प्रारंभ

● प्रवेश के लिए पालक कर सकते हैं संपर्क

कांकेर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिले के एकमात्र विशेष शासकीय दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित 50 सीटर आवासीय विद्यालय में कक्षा पहली से आठवी तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं, संस्था में नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9वीं की पढ़ाई भी प्रारंभ की गई है। दिव्यांग बच्चों की विशेष एवं सुगम्य शिक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की पहल पर स्थापित स्मार्ट क्लास के माध्यम से ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, विज्ञान, गणित तथा अन्य विषयों का अध्ययन-प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से कराया जा रहा है। इसके अलावा चित्रकला, संगीत, कंप्यूटर, नृत्य, क्राप्ट और अन्य सहगामी गतिविधियों में भी विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा पहली से नवमीं तक शिक्षण शुरू होने पर विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों में भी खुशी व्यक्त किया है। श्रवणबाधित विद्यार्थियों ने सांकेतिक भाषा के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

उपसंचालक समाज कल्याण ने बताया कि जिले के एकमात्र आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं सुगम्यता हेतु विशेष विद्यालय में कक्षा पहली से 9वीं तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। अभिभावक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ आवास, भोजन, बिस्तर, गणवेश, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, स्पीच थैरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों सहित ब्रेल और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7587309685 पर संपर्क किया जा सकता है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम मसपुर में 'मायका सेंटर' का किया शुभारंभ

● गर्भवती माताओं को मिलेगी सुरक्षित मातृत्व की सुविधा

नारायणपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, संसदीय कार्य एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने विकासखंड ओरछा के ग्राम मसपुर में नवस्थापित 'मायका सेंटर' का विधिवत उद्घाटन किया। जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत स्थापित यह केंद्र दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य जांच, पोषण, परामर्श और समय पर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे ही जिला नारायणपुर में ग्राम मसपुर, बोरनिरपी, ईरकभट्ठी, आदेर, कुड़मेल, मोहंदी और रेखावाया में मायका सेंटर खोला गया है।

उद्घाटन अवसर पर बताया गया कि मायका सेंटर में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व सुरक्षित आवास, 24म7 स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) की विशेष देखरेख, पौष्टिक भोजन, आवश्यक दवाइयां, स्वास्थ्य परामर्श, नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला अस्पताल या प्रसूति केंद्र तक रेफरल एवं परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मायका सेंटर मसपुर में वर्तमान में तीन हितग्राही भर्ती हैं। इनमें दशरी हिचामी, जुर्री ध्रुवा और सोनी ध्रुवा शामिल हैं। इन महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों की प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना है। मायका सेंटर जैसी पहल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी तथा ग्रामीण और आदिवासी अंचलों की महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्णभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस जनहितकारी पहल के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका के अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के पार्षदगण, कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, संयुक्त कलेक्टर डॉ सुमित गर्ग, सीएमएचओ डॉ. टी.आर. कुंवर सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।

16 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बीजापुर। कलेक्टर विश्वदीप द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के परिजनों को 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अर्न्तगत सर्पदंश से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतिका मनीषा गुरला के निकटतम वारिस उनके पति संपत गुरला को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। इसी तरह आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतिका मल्ली कलमू के निकटतम वारिस उनके पुत्र पिड़गा कलमू, तालाब में डुबने से मृत्यु के दो प्रकरणों मे से मृतक विष्णु कतलाम के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती मिटकी कतलाम एवं मृतक अडला चन्दैया के निकटतम वारिस उनके पुत्र संजय अड़ला सहित प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये कुल 16 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। राशि का भुगतान संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।

चारामा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन की बैठक

पदोन्नति और शोषण के मुद्दे पर हुई चर्चा

चारामा। ब्लॉक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन चारामा की एक महत्वपूर्ण बैठक कर्मचारी भवन चारामा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन की अध्यक्ष योगिता यादव ने की। बैठक में संगठन के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासन द्वारा लागू समयमान क्रमोन्नति एवं वेतनमान के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत कर कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाएगा।

बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर निर्णय लिए गए: 1. समयमान वेतनमानः शासन के नियमों के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर क्रमोन्नति और वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए रणनीति बनाई गई।

2. शिक्षा विभाग में पदोन्नतिः शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है। इसके लिए आगामी समय में कड़ी रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

3. मध्यान्ह भोजन में शोषण का विरोधः बैठक में सबसे गंभीर मुद्दा माध्यमिक विद्यालयों में उठा। बताया गया कि रसोइयों के अनुपस्थित रहने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से दबावपूर्वक मध्यान्ह भोजन बनवाया जा रहा है। संगठन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है और इसे तत्काल बंद किया जाए।

उपस्थित पदाधिकारीः बैठक में अध्यक्ष योगिता यादव, उपाध्यक्ष हामुराम चेलक, सचिव नरेन्द्र मरकाम, सह-सचिव नूतन कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गनवीर, सलाहकार यामिनी साहू, नेहा नाविक, अजीत खिन्टे, भुनेश्वर पिद्दू, नरोत्तम दास, राधेश्याम तिवारी एवं मीडिया प्रभारी उमेश साहू, हेमंत नेताम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित

नारायणपुर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागरिकों, संस्था एवं संगठन को सम्मानित करने के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमत्रित किए हैं। समाज कल्याण विभाग ने जिले के पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन नामांकन करें। 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाईन नामांकन प्रस्तुत कर सकते है, इसके लिए आवेदकों को भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने समाज में एकता और अंखडता को बढ़ावा दिया है।

कोण्डागांव में शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीयन पर जोर

● कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली
● राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की

कोण्डागांव। कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों एवं एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण, अविवादित एवं विवादित नामांतरण, डिजिटल हस्ताक्षर, अधिकार अभिलेख वितरण सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण कर उन्हें योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने फील्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर कार्य में तेजी लाने और कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम अजय उरांव, संयुक्त कलेक्टर वहीदुर्रहमान, एसडीएम केशकाल सुश्री आकांक्षा नायक सहित राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रकाश कुमार उइके 15 को जिले के प्रवास पर

कांकेर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के वरिष्ठ सलाहकार-सह-एपीएस प्रकाश कुमार उइके 15 जुलाई को जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री उइके जिले की सभी वन प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर वन धन केंद्रों के संचालन एवं गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके पश्चात वे जिले की सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े विभिन्न विषयों एवं जन-शिकायतों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

विधायक और कलेक्टर ने बाजार का किया निरीक्षण

● सुव्यवस्थित और पुनर्विकास कार्य की तैयारी

कोंडागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी तथा कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने रविवार को नगर के बाजारपारा क्षेत्र में बाजार के सुव्यवस्थित पुनर्विकास कार्य के लिए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन करते हुए आम नागरिकों, व्यापारियों एवं ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखकर समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बाजार परिसर में आधुनिक एवं व्यवस्थित बाजार शेड के निर्माण, बेहतर विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग विकसित करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इस अवसर पर मनोज जैन, सुश्री सोनामणि पोयाम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सचिन गुप्ता तथा राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बरसों की राह हुई आसान

पुलिया निर्माण से धनगोल को मिली नई जिंदगी

बीजापुर। ग्राम पंचायत अंगमपल्ली के आश्रित ग्राम धनगोल में वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या अब अतीत बन गई है। मनरेगा एवं विशेष केंद्रीय सहायता एससीए के अभिसरण से निर्मित 6 मीटर लंबी पुलिया ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब बारिश के मौसम में भी गाँव का मुख्यालय से संपर्क बना रहता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक आवागमन की सुविधाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो गई हैं।

धनगोल के ग्रामीण लंबे समय से वर्षा ऋतु में मार्ग पर पानी भर जाने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बरसात के दौरान गाँव का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता था, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों की कृषि गतिविधियाँ, मरीजों को समय पर उपचार तथा ग्रामीणों की दैनिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित होती थीं। ग्रामीणों की इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए मनरेगा एवं विशेष केंद्रीय सहायता एससीए के अभिसरण से धनगोल मार्ग पर 6 मीटर पुलिया का निर्माण कराया गया। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 17.63 लाख रुपये रही, जिसमें मनरेगा से 7.63 लाख रुपये तथा एससीए से 10 लाख रुपये का योगदान दिया गया। निर्माण कार्य का शुभारंभ 2 जनवरी 2026 को हुआ।

यह परियोजना केवल आधारभूत अधोसंरचना के विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्माण अवधि के दौरान स्थानीय रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनी। कार्य में 18 जॉब कार्डधारी परिवारों के 94 श्रमिकों को रोजगार मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

कांकेर के जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर 300 छात्र

● नए भवन की मांग अधूरी, बारिश में टपकती छत और झड़ता प्लास्टर बढ़ा रहा खतरा

कांकेर। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के ग्राम पुरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। करीब 300 छात्र-छात्राएं इसी असुरक्षित भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां छत से प्लास्टर गिरने और दरारों के कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। बरसात के दौरान स्कूल की छत से पानी टपकता है और कई कमरों की खिड़कियां भी टूट चुकी हैं। शिक्षक छत पर तिरपाल डालकर किसी तरह कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। पहले भी कई बार प्लास्टर टूटकर बच्चों के पास गिर चुका है।

वर्षों से नए भवन की मांग : ग्रामीण पिछले चार-पांच वर्षों से नए स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक भवन की स्वीकृति नहीं मिली।

सरपंच ने उठाया मुद्दा : ग्राम पंचायत पुरी के सरपंच दीपक गावड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार आवेदन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मद्रास हाईकोर्ट के गोवध प्रतिबंध के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में कहीं भी बकरीद या किसी अन्य दिन गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पूरे राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने?

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का अंतिम पैराग्राफ, जिसमें राज्यभर में प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, प्रथम दृष्टया सुधार की मांग करता है। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।

सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर क्या आपत्ति जताई?

राज्य सरकार ने दलील दी कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत है। इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र की उन गायों के वध की अनुमति दी जाती है, जो काम करने और प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हों। सरकार ने यह भी कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु क्रूरता निवारण (वध गृह) नियम, 2001, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998 तथा तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 जैसे अन्य कानून वध की प्रक्रिया और शर्तों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनमें कहीं भी पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। राज्य का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाकर हाई कोर्ट ने वैधानिक कानून की जगह न्यायिक कानून बना दिया।

हाईकोर्ट ने यह आदेश कब और किस याचिका पर दिया था?

मद्रास हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण शामिल थे, ने 27 मई को बकरीद से ठीक पहले यह आदेश

पारित किया था। यह फैसला हिंदू मक्कल काची के महासचिव के. सूर्या प्रशांत द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनाया गया था। याचिकाकर्ता ने केवल यह मांग की थी कि वध निर्धारित स्थानों पर ही कराया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इससे आगे बढते हुए गायों और बछड़ों के वध पर कहीं भी और किसी भी दिन पूर्ण प्रतिबंध लगाने का व्यापक आदेश दे दिया।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में किस आधार का हवाला दिया था?

आदेश पारित करते समय हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गो वध पर प्रतिबंध आवश्यक है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि बकरीद के अवसर पर गो वध इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

राज्य सरकार ने कानूनी दलील में क्या कहा?

राज्य सरकार ने कहा कि जब मौजूदा कानून निर्धारित स्थानों पर गायों की एक विशेष श्रेणी के वध की अनुमति देता है, तब उसके विपरीत कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जा सकता। सरकार ने यह भी आपत्ति जताई कि हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश संख्या 1715 पर भरोसा किया, जबकि उसकी वैधता या लागू होने का सवाल अदालत के सामने कभी उठा ही नहीं था। सरकार का कहना है कि कोई भी कार्यकारी आदेश राज्य में लागू कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

क्या हाई कोर्ट ने याचिका के दायरे से बाहर जाकर फैसला दिया?

स्पेशल लीव पिटिशन में राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका केवल कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने तक सीमित थी। इसके बावजूद डिवीजन बेंच ने मामले का दायरा बढाते हुए पूरे राज्य में गायों के वध पर हर परिस्थिति में प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक कि अधिकृत बूचड़खानों में भी, जबकि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई राहत नहीं मांगी थी। सरकार का कहना है कि अदालत ने ऐसी राहत प्रदान कर दी, जिसके लिए न तो कोई प्रार्थना की गई थी और न ही उस पर बहस हुई थी।

फैसले को विरोधाभासी क्यों बताया गया?

राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले के एक हिस्से में यह माना कि जानवरों का वध केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसने यह भी निर्देश दिया कि बकरीद या किसी भी अन्य दिन कोई गाय या बछड़ा नहीं काटा जाना चाहिए। सरकार के अनुसार, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं और फैसला स्वयं ही विरोधाभासी हो जाता है।

पुलिस की तैयारी को लेकर सरकार ने क्या कहा?

याचिका में सरकार ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध किया जा रहा था या किया जाएगा, जबकि पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट कहा था कि पहले से ही सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। सरकार के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का वध न हो और धार्मिक बलि केवल बंद तथा सार्वजनिक नजर से दूर स्थानों तक ही सीमित रहे। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष राज्य द्वारा पेश किए गए तथ्यों के विपरीत है।

'खेला होबे' की जगह 'आयुष्मान दिवस'

ममता बनर्जी के एक और फैसले को सीएम शुभेंदु ने पलटा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि उनकी सरकार केंद्र सरकार की जन स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्मान में 16 अगस्त को 'आयुष्मान दिवस' के रूप में मनाएगी। यह कदम पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार द्वारा मनाए जाने वाले 'खेला होबे दिवस' की परंपरा को समाप्त करेगा।

16 अगस्त को ही आयुष्मान दिवस क्यों मनाया जाएगा?

यह दिन राज्य में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने का भी प्रतीक होगा। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था।

16 अगस्त को 'काला दिन' क्यों बताया गया?

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तमलुक में भाजपा की एक विशेष संगठनात्मक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारी ने कहा, '16 अगस्त कोलकाता के इतिहास का एक काला दिन है, क्योंकि इसी तारीख को सुहरावर्दी के नेतृत्व में 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' हुई थी। पिछली टीएमसी सरकार इस दिन को 'खेला होबे दिवस' के रूप में मनाती थी। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अब इस दिन को 'आयुष्मान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। '

1946 में 16 अगस्त को क्या हुआ था?

अधिकारी 16 अगस्त 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित 'डायरेक्ट एक्शन डे' का जिक्र कर रहे थे। उस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल और आर्थिक गतिविधियां बंद कर प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया था।

'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' कैसे हुई थी?

राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह घटनाक्रम जल्द ही ब्रिटिश भारत की सबसे भीषण सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, जिसे 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' के नाम से जाना जाता है। कई दिनों तक कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक झड़पें होती रहीं।

इस हिंसा में कितना बड़ा नुकसान हुआ था?

हालात सामान्य होने तक करीब 4,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, 10,000 से अधिक लोग घायल हुए थे और हजारों परिवार बेघर हो गए थे। इस हिंसा ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया तथा इसे भारत के विभाजन की प्रक्रिया को तेज करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में माना जाता है।

सुहरावर्दी कौन थे और उनका क्या संबंध था?

मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी उस समय ब्रिटिश भारत के अविभाजित बंगाल प्रांत के मुख्यमंत्री थे।

'खेला होबे दिवस' की शुरुआत कैसे हुई थी?

हाल के वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद 16 अगस्त को 'खेला होबे दिवस' घोषित किया था। इसका उद्देश्य युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना और जीत का जश्न मनाना बताया गया था। हालांकि, राज्य के तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में यह दिन कई बार राजनीतिक टकराव और हिंसा से भी जोड़ा गया।

केपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने किया निलंबित, सरकारी नौकरी में बेटियों की अवैध भर्ती का आरोप

बंगलूरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कथित तौर पर अवैध तरीके से चयनित कराने में मदद की। राज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट में संदर्भ भेजने की भी सिफारिश की है।

क्या है राज्यपाल का फैसला?

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य केपीएससी अध्यक्ष के दायित्व निभाएंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए साहूकार को निलंबित करना आवश्यक है।

राज्यपाल के आदेश में क्या कहा गया है?

राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत भारत के सर्वोच्च

न्यायालय को इस मामले में आवश्यक जांच के लिए संदर्भ भेजने की सिफारिश की है। यह जांच केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी होगी।

साहूकार पर कौन से आरोप लगे हैं?

राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, साहूकार के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें आरोप लगाया गया कि साहूकार ने अपनी दो बेटियों के इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कथित गैरकानूनी चयन में भूमिका निभाई। इन शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

हितों के टकराव को लेकर क्या आरोप है?

आदेश में कहा गया है कि साहूकार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी दोनों बेटियों के उम्मीदवार होने के बावजूद न तो खुद को चयन प्रक्रिया से अलग किया और न ही हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) की औपचारिक जानकारी दी। इसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना गया है।

आय और जाति प्रमाणपत्र को लेकर क्या दावा किया गया है?

आदेश के मुताबिक, साहूकार की एक बेटी ने परिवार की वार्षिक आय केवल 40 हजार रुपये बताकर आय और जाति प्रमाणपत्र हासिल किया। इसके आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण और क्रीमी लेयर से छूट का लाभ लिया। आरोप है कि उस समय उसके पिता केपीएससी अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन इस तथ्य को छिपाया गया।

सरकारी नियम क्या कहते हैं?

राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि 30 मार्च 2002 के सरकारी आदेश के अनुसार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बच्चों को कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली के अलीपुर में बड़ा हादसा

नहाते समय यमुना नदी के तेज बहाव में बहे चार बच्चे

- अब तक कोई सुराग नहीं

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में हिरंकी गांव के पास ठोकर नंबर 24 के निकट यमुना नदी में नहाते समय चार नाबालिग लड़के तेज बहाव में बह गए। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। रविवार को कई घंटों तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। अंधेरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से सर्च ऑपरेशन रात करीब 10:30 बजे रोक दिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम लगभग 07:46 बजे चार लड़कों की यमुना में डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। घटना स्थल पर पहुंचने पर पता चला कि पांच नाबालिग लड़के यमुना नदी में नहाने के लिए ठोकर नंबर 24 पर गए थे। नदी में तेज बहाव के कारण

चार बच्चे, राहुल (15), अंशु (15), सौरभ (15) और अमनदीप (15), गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे। बहाव इतना तेज था कि वह नदी में डूबते ही चले गए। पांचवां बच्चा लकी (14), जो किनारे पर था, उसने शोर मचाया। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चारों बच्चे पानी में समा चुके थे।

सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, डीडीएमए, दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के दूसरे दिन भी बच्चों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं है।

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात: पुलिस के जवान ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या

- कार से बीच सड़क शव फेंककर हुआ फरार

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दिल्ली पुलिस के एक जवान ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी मनीष भाटी दिल्ली पुलिस के पूर्वी दिल्ली जिला एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड) में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है।

जानकारी के अनुसार, ईस्ट विनोद नगर, गली नंबर 2 निवाली मनीष की पत्नी की सोमवार तड़के तबीयत बिगड़ गई थी। उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल जाते समय रास्ते में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच

गहरा विवाद हो गया। इसी विवाद के दौरान मनीष भाटी ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोली मारने के बाद मनीष भाटी ने अपनी पत्नी के शव को बीच सड़क पर फेंक दिया और अपनी कार में बैठकर फरार हो गया। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी।

फिलहाल, पुलिस आरोपी मनीष भाटी की तलाश में जुटी हुई है। इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एनएससीबीआई एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में प्रवेश व नमाज पर लगी रोक

कोलकाता। कई वर्षों की बातचीत के बाद, रनवे का विस्तार करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल (एनएससीबीआई) एयरपोर्ट इलाके से 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार से एयरपोर्ट के रास्ते मस्जिद में जाने के लिए एंट्री पास बंद कर दिए गए हैं। मस्जिद के अंदर नमाज भी रोक दी गई है। दमदम उत्तर के विधायक सौरव सिकदर शनिवार सुबह इलाके में मौजूद थे, और उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बात की। बाद में, विधायक ने कहा कि नमाज पढ़ने आने वाले ज्यादातर लोग इस कदम से सहमत हैं।

लोगों से भड़काऊ बयानबाजी न करने की अपील

उन्होंने कहा कि इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया

जा रहा है और अपील की कि इस घटना को लेकर कोई भड़काऊ बात न की जाए। 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को 'बांकरा मस्जिद' के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही स्थित है। लंबे समय से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही है। दम-दम एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं; मुख्य (बड़ा) रनवे टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा रनवे छोटा है। मस्जिद उस रनवे से थोड़ी दूरी पर स्थित है।

क्यों बदली जा रही मस्जिद की जगह?

जानकारों का कहना है कि अगर मरम्मत के लिए पहला रनवे कुछ समय के लिए बंद किया जाता है तो बड़े विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आएंगी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि मस्जिद से भी टेक-ऑफ और लैंडिंग करने वाले विमानों को खतरा है, और दूसरे रनवे को बड़ा करने का काम भी रुका हुआ है। कई दशकों से मस्जिद को हटाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं हो पाया है।

राज्य में सरकार बदलने के बाद, एनएससीबीआई एयरपोर्ट के अंदर से मस्जिद को हटाने के लिए कदम उठाए गए। एयरपोर्ट अधिकारियों और प्रशासनिक हलकों में बैठकें भी हुईं।

प्रथम पेज का शेष

विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर..

कॉलेजों को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और 13 महाविद्यालयों में इन्हें शुरू करने की संभावना है।

सत्र के दूसरे दिन यानी आज कांग्रेस (14 जुलाई) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में भाजपा के स्पष्ट बहुमत के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके जरिए कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।

डॉ. तीजन बाई को दी गई...

भागीदारी अत्यंत सीमित थी, उस समय उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनीं। डॉ. तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोकसंस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला एवं सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।

नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यह सदन में पहला अवसर है, जब हम किसी पदम् सम्मान से सम्मानित विभूति पर चर्चा कर रहे हैं। डॉ. तीजन बाई का जाना हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपने विधायक दल की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सँस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ का गौरव विश्व पटल पर स्थापित किया। मैं अपने मंत्रालय की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ऐसे परिवार से थीं, जहाँ शिक्षा का अभाव रहा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश को गौरान्वित किया। उनका जीवन कर्म हम सबके लिए प्रेरित करने वाला है।

संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का जीवन बेहद संघर्षमय रहा है। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने पंडवानी गायन के माध्यम से खुद को स्थापित किया। छत्तीसगढ़ को गौरांवित किया। उनका जाना पूरी दुनिया लोक कला के लिए एक बड़ी क्षति है।

2020 दिल्ली दंगा मामले में...

गैरकानूनी जमाव के साझा उद्देश्य से अपराध करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। कासिम, जावेद और अनस को भी दंगा, घातक हथियार के साथ दंगा, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण, हत्या और गैरकानूनी जमाव के साझा उद्देश्य से अपराध करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया।

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हिंसक भीड़ ने उनकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शियों, फोरेंसिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने पांच आरोपितों को दोषी और छह को बरी करने का फैसला सुनाया। अब दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा पर अलग से सुनवाई होगी।

अब शिक्षा में क्रांति का...

आगे कहा कि जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यहां दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों को ठेके और तरक्की मिलती है। लेकिन सजा किसे मिलती है? उन छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री यह सब देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने चुप्पी चुनी है। जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा है। अब बहुत हुआ। अब शिक्षा में क्रांति का वक्त है। राहुल गांधी ने छात्रों से अपील की कि वे 17 जुलाई को देहरादून में उनसे जुड़ें और छात्रों की गूंज अभियान को और मजबूत बनाएं।

राहुल गांधी ने 17 जून को राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज की पहली रैली को संबोधित किया था। वह आगे भी दूसरे शहरों में ऐसी रैलियों को संबोधित करेंगे। कोटा की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था चयन की व्यवस्था नहीं, बल्कि अस्वीकृति की व्यवस्था बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह छात्रों और मध्यम वर्ग के परिवारों पर जरूरत से ज्यादा आर्थिक बोझ और तनाव डालती है। उन्होंने यह भी कहा था कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक तनावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा था, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक वसूली की मशीन बन गई है। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जो आपको बड़े सपने देखने का अवसर दे। उन्होंने यह भी कहा था कि देश के युवाओं को बहुत अधिक दुख, तनाव और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बच्चों पर दबाव डालती है, उन्हें तनाव देती है और उनका मनोबल तोड़ देती है।

एक महीने में 12 बच्चों की...

संदिग्ध लक्षणों वाले बच्चों की कुल 6 मौतें दर्ज की गई हैं। जबकि तीन बच्चों की मौत गोधरा के सिविल अस्पताल में हुई। इनमें दो बच्चों की मौत दो दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को हुई। इन दोनों बच्चों में एक बच्चे की उम्र 1 साल और दूसरे की उम्र दो साल थी।

अब तक 27 संदिग्ध मरीजों के नमूने गांधीनगर भेजे गए हैं, जिनमें से 19 की जांच हो चुकी है। इनमें से 7 पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए 7 मरीजों में से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। शेष 8 नमूनों की जांच अभी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई।

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामला

आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार

- पूछताछ के लिए लाया गया कार्यालय

चमोली। बदरीनाथ धाम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर रात करीब 11 बजे आरोपी को पुलिस ने देहरादून से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बदरीनाथ कार्यालय लेकर आई है।

साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। उसके संभावित जगहों पर भी लगातार दबिश दी जा रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसे देहरादून से गिरफ्ता किया गया। आरोपी के पास से एक शालिग्राम शिला और एक लैपटॉप

बरामद किया गया है। मेडिकल कराने के बाद पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी।

मंदिर में चढ़ावे के रखरखाव और जमा प्रक्रिया के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के संकेत मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार प्रयास कर रही थी।

तिरछी नज़र से

टैक्स देने वाले की आत्मकथा

एक ईमानदार करदाता की जीवन-गाथा – जो जीते जी शहीद हो गया

प्रभात दत्त झा

मेरा नाम रामावतार वर्मा है। मैं ईमानदारी से टैक्स भरता हूँ। आप यह पढ़कर हँस रहे हैं- मैं समझता हूँ। इस देश में ईमानदारी से टैक्स भरने वाला आदमी या तो बहुत बड़ा मूर्ख होता है, या बहुत बड़ा साहसी। मैं दोनों हूँ।

मेरी कहानी 1 अप्रैल से शुरू होती है - और हर वर्ष उसी दिन मुझे यह अहसास होता है कि यह तारीख यूँ ही नहीं चुनी गई। जब ITR भरने बैठता हूँ, तो लगता है जैसे किसी ने मेरे नाम पर अप्रैल फूल मनाया हो। फॉर्म खोलता हूँ-उसमें इतने कॉलम हैं जितने मेरे पड़ोसी के पाँच बेटे, तीन बेटियाँ और सात नाते-रिश्तेदार मिलकर नहीं बनाते।एक ईमानदार करदाता की पहचान यह है कि वह टैक्स भरते समय रोता है, और टैक्स न भरने वाला टीवी पर मुस्कुराता हुआ नज़र आता है।

Section 80C, 80D, 80G, 80CCC, 80CCD - यह धाराएँ हैं या किसी हाईवे के किलोमीटर? CA साहब बोलेः यहाँ बचत होती है। मैंने पूछाः कितनी? बोलेः डेढ़ लाख तक निवेश कर सकते हो। मैंने कहाः निवेश के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएँ जब आधा वेतन ञ्ठष्ट में गया? CA साहब ने आँखें झुकाईं और बोलेः आपसे बड़ी फ़ीस नहीं लूँगा।

मेरे पड़ोसी चंदूलाल जी हैं। तीन दुकानें हैं, नकद में व्यापार है, बेटे की शादी में सोने के जेवर थे जो एक छोटी सुनार की दुकान को शर्मिंदा कर दें। उनका टैक्स? बोलेः भाई, हमारा तो घर का खर्च ही इतना है कि बचत होती नहीं। मैं सोचता हूँः घर का खर्च बीएमडब्लू कार, विदेश-यात्रा और इनवर्टर-बैटरी के नाम पर होता है, लेकिन टैक्स तब भी शून्य। यह चमत्कार है या कला? शायद दोनों।

एक बार मैंने नोटिस पाया। Income Tax विभाग ने पूछाः आपने इस वर्ष FD तोड़ी, उसका स्रोत बताइए। मैंने बतायाः यह मेरी माँ के गहने बेचकर मिले पैसे थे जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आए। जवाब आयाः प्रमाण प्रस्तुत करें। मैं प्रमाण ढूँढने गया तो अस्पताल ने कहाः रसीद छह महीने से पुरानी है, अब नहीं मिलेगी। मैं समझ गयाः ईमानदारी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा मिलती ज़रूर है, बस समय अलग-अलग होता है।

सरकार कहती हैः टैक्स दो, देश बनाओ। मैं टैक्स देता हूँ। सड़क टूटी है- मरम्मत नहीं। अस्पताल में दवा नहीं- ख़रीदनी पड़ती है। बच्चे के स्कूल में टीचर नहीं - ट्यूशन लगानी पड़ती है। यानी एक बार टैक्स में दिया, दूसरी बार बाज़ार में दिया। मैं बिना किसी शिकायत के देश का निर्माण कर रहा हूँ - ज़मीन पर भी, कागज़ पर भी।

एक दिन मैं मर जाऊँगा। ITR नहीं भर पाऊँगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि Income Tax विभाग उस वर्ष भी एक नोटिस भेजेगाः श्री रामावतार वर्मा, आपने इस वर्ष ITR दाखिल नहीं किया। कारण बताएँ। उस नोटिस का जवाब मेरी आत्मा देगीः महोदय, मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है। कृपया अब छोड़ें।

हाँ, मैं जानता हूँ - विभाग उस मृत्यु प्रमाण-पत्र पर भी सवाल उठाएगा कि यह मूल है या स्व-प्रमाणित? फिर मेरे बच्चों को वार्षिकी (Annuity) दिखानी पड़ेगी कि पिताजी सच में मरे थे या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गायब हो गए।

ईमानदार करदाता – वह प्राणी जो देश के लिए जीता है, देश के लिए टैक्स देता है, और देश उसे अकेला छोड़ देता है।

किताबी ज्ञान से आगे

कौशल आधारित शिक्षा क्यों है समय की सबसे बड़ी ज़रूरत

रविकान्त ठाकुर

आज का युवा किताबों की दुनिया में खोया रहता है, लेकिन जीवन की असली मंच पर उतरते ही अक्सर ठिठक जाता है। डिग्री हाथ में है, पर आत्मविश्वास और दक्षता का अभाव। क्या सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काफी है? आज का युग तेज़ परिवर्तन, तकनीकी क्रांति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है। ऐसे में कौशल आधारित शिक्षा न केवल समय की मांग है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम भी।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था- 'शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।' यह कथन स्पष्ट बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी भरना नहीं, बल्कि व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करना है। महात्मा गांधी की 'नई तालीम' भी शिक्षा को श्रम, कौशल और वास्तविक जीवन से जोड़ने पर आधारित थी।

पारंपरिक शिक्षा की सीमाएं

पारंपरिक व्यवस्था में लंबे समय तक रट्टा मारकर परीक्षा पास करना मुख्य लक्ष्य रहा है। नतीजा? डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन रोजगार पाने, समस्याओं का समाधान करने, टीम में काम करने या नई परिस्थितियों में खुद को ढालने जैसे जरूरी कौशल नहीं विकसित होते। उद्योग और समाज ऐसे युवाओं की तलाश में हैं जो ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास भी रखते हों।

सरकारी PLFS 2025 के अनुसार शिक्षित युवाओं (माध्यमिक और उच्चतर) में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत के आसपास है, जो यह स्पष्ट करता है कि केवल डिग्री पर्याप्त नहीं।

कौशल शिक्षा का असली रूप

कौशल आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को परियोजना कार्य, प्रयोग, इंटर्नशिप और वास्तविक जीवन के अनुभवों के जरिए सीखने का अवसर देती है। इसमें समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, संचार कौशल, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता जैसे गुण विकसित होते हैं। जब कोई छात्र खुद करके सीखता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और ज्ञान जीवन में उतरने लगता है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं को याद दिलाया था- 'सीखना रचनात्मकता देता है, रचनात्मकता सोच की ओर ले जाती है, सोच ज्ञान देती है और ज्ञान आपको महान बनाता है।' आज के डिजिटल युग में AI, कोडिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, डेटा विश्लेषण और वित्तीय साक्षरता जैसे कौशल भविष्य की नौकरियों के लिए अनिवार्य हो गए हैं।

विश्व के सफल अनुभव

दुनिया कई देशों से सीख सकती है। जर्मनी का डुअल सिस्टम (स्कूल+कंपनी में व्यावहारिक प्रशिक्षण) इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां युवा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ कार्यस्थल पर सीधे अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर कम हो जाता है।

भारत में सकारात्मक बदलाव

भारत की नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह स्कूल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, स्थानीय कला-शिल्प और इंटर्नशिप को प्रोत्साहन देती है। इस नीति के तहत अब स्कूल स्तर से व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हजारों स्कूलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसका लक्ष्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो ज्ञान को सही जगह उपयोग कर सकें और सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था- 'उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है।' कौशल शिक्षा ठीक यही काम करती है- ज्ञान को जीवन से जोड़ती है।

कौशल शिक्षा के दूरगामी लाभ

यह शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित नहीं। यह आत्मनिर्भरता, निरंतर सीखने की आदत, नवाचार और आत्मविश्वास पैदा करती है। ऐसा युवा न केवल खुद के लिए अवसर पैदा करता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

प्राचीन भारत में भी शिक्षा केवल किताबी नहीं थी। गुरुकुलों में व्यावहारिक ज्ञान, शिल्प और जीवन कौशल पर जोर दिया जाता था। आज हमें उसी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में अपनाना है।

'मैंने सुना, भूल गया। मैंने देखा, याद रहा। मैंने किया, तो सीख गया।'

यही कौशल आधारित शिक्षा का मूल मंत्र है। अंत में इन पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगाः-

'देश के शिल्पी हैं हम,
हमें मूर्तियाँ यूं गढ़ लाना है ।
करे जो तन मन पावन,
सबल वही परिवर्तन लाना है॥'

शिक्षाविद,अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ,
प्रेरक वक्ता एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक

रिटायरमेंट की उम्र तय हो सकती है, सीखने की नहीं

60+ के बाद भी सीखते रहिए, क्योंकि सक्रिय दिमाग ही खुशहाल और स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है । 'सरकारी नियम आपकी नौकरी की सेवानिवृत्ति तय कर सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान, जिज्ञासा और सपनों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती।'

सुलक्षणा जिल्लारे

समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का सीखने और आगे बढ़ने का समय समाप्त हो जाता है। लेकिन आज का युग इस सोच को पूरी तरह बदल रहा है। बढ़ती जीवन-प्रत्याशा, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ऑनलाइन शिक्षा ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। वास्तव में, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह उम्र से पहले ही स्वयं को सीमित कर लेता है।

रिटायरमेंट केवल नौकरी का अंत है, जीवन का नहीं। यह वह समय है जब वर्षों के अनुभव के साथ नई चीज़ें सीखकर व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल उद्यमी बन रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, नई भाषाएँ सीख रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव है, और नई तकनीक उस अनुभव को नई उड़ान देती है।

दिमाग भी शरीर की तरह अभ्यास चाहता है

जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए निरंतर सीखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मस्तिष्क जीवनभर नई जानकारी ग्रहण करने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity) कहा जाता है।

जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, नई तकनीक समझते हैं या किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं, तब मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इससे स्मरण शक्ति, ध्यान, समस्या-समाधान की क्षमता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है।

कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि मानसिक रूप से सक्रिय जीवनशैली उम्र बढ़ने के साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है। सीखना तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में उद्देश्य का भाव बनाए रखने में भी सहायक होता है।

डिजिटल युग में अनुभव सबसे बड़ी ताकत है

आज AI और नई तकनीकें तेजी से दुनिया बदल रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल युवाओं के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुभव और तकनीक का मेल सबसे प्रभावशाली परिणाम देता है। जिस व्यक्ति के पास जीवन का अनुभव है, यदि वह नई तकनीक भी सीख ले, तो वह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।

दादा-दादी और नाना-नानी यदि डिजिटल माध्यमों से जुड़ते हैं, तो वे अपने बच्चों और पोते-पोतियों से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। वे ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक गतिविधियों का लाभ भी अधिक सहजता से उठा सकते हैं।

60+ के बाद क्या सीखें?

आज विकल्पों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हर वरिष्ठ नागरिक के लिए उपयोगी हो सकते हैं :-

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक की मूल बातें
- कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट का बेहतर उपयोग
- ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा
- नई भाषा सीखना
- लेखन, ब्लॉगिंग या पुस्तक लेखन
- चित्रकला, संगीत, फोटोग्राफी और हस्तशिल्प
- योग, ध्यान और स्वास्थ्य प्रबंधन
- वित्तीय योजना और निवेश की समझ
- सार्वजनिक वक्तृत्व, शिक्षण और मेंटरिंग
- सोशल मीडिया का सुरक्षित और सकारात्मक उपयोग

इनमें से कोई भी कौशल केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी बन सकता है।

सीखना केवल करियर के लिए नहीं, जीवन के लिए है

बहुत से लोग सोचते हैं कि सीखने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सीखना जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का माध्यम है। जब व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है, तो उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर दिन एक नया उद्देश्य मिलता है। यही उद्देश्य मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है।

आज ही शुरुआत करें

सीखने के लिए किसी बड़े संस्थान या महंगे कोर्स की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ना, कोई ऑनलाइन वीडियो देखना, नई तकनीक का अभ्यास करना, पुस्तकालय जाना, किसी कार्यशाला में भाग लेना या किसी नई कला को सीखना—ये छोटे-छोटे कदम भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

हर नया कौशल केवल ज्ञान नहीं बढ़ाता, बल्कि यह संदेश भी देता है कि इंसान तब तक जवान है, जब तक उसकी जिज्ञासा जीवित है।

निष्कर्ष :

रिटायरमेंट जीवन की गति को धीमा करने का नहीं, बल्कि नई दिशा देने का अवसर है। यह वह समय है जब अनुभव, समय और जिज्ञासा मिलकर एक नई पहचान बना सकते हैं।

आइए, हम उम्र की सीमाओं को नहीं, अपनी संभावनाओं को पहचानें। क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है, जो हर उम्र में सीखना, बदलना और आगे बढ़ना जानते हैं।

(सुलक्षणा जिल्लारे - रंगों, पत्थरों और धागों से अनोखी कृतियां तैयार करना। विशिष्ट कला प्रतिभा और बच्चों को कला का प्रशिक्षण)

प्रेरक पंक्तियाँ

'उम्र सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलती है, सीखना इंसान की पहचान बदल देता है।'

'रिटायरमेंट नौकरी से होता है, जिज्ञासा से नहीं।'

'जब तक सीखना जारी है, तब तक जीवन आगे बढ़ता रहता है।'

'ज्ञान वह निवेश है, जिसका लाभ जीवनभर मिलता है।'

पुस्तकालयों को फिर से आबाद करने की जरूरत

'किताबें जगाती हैं बंद अलमारी के शीशे से बड़ी हसरत से ताकतीं हैं'......मशहूर गीतकार गुलजार के गाने की यह पंक्तियां आज के बदलते हुए डिजिटल दौर में एकदम सटीक बैठती हैं आज इंटरनेट सोशल मीडिया और चंद् सेकंड की रील ने किताबों से हमारे लगाव को , एक एहसास को, पाने की खुशबू और किताबों में रखे उन छोटे-छोटे लम्हों को हमसे दूर कर दिया है। सूचनाएं अब हमारी उंगलियों पर नाचती हैं , परंतु यही विषय वस्तु मानव में धैर्य की कमी को विकसित कर रही है । ऐसे में समाज में (reading culture) पठन संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए ग्रंथालयों में जान भरना आवश्यक है।

हमारे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी और शिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाने वाला 'हमर बिलासपुर' में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आता है । बिलासपुर न केवल स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है बल्कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी गढ बन गया है हमारे शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय साथ ही कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे डॉक्टर सी. वी.रमन विश्वविद्यालय और जरहाभाटा स्थित शासकीय जिला ग्रंथालय साथ ही कई शासकीय स्कूलों और प्राइवेट स्कूलो के ग्रंथालय भी उनके जीवंत उदाहरण है।

यदि हम उपरोक्त संस्थाओं एवं पुस्तकालयों की स्थिति पर एक नजर डालें तो हकीकत और ही निकलकर सामने आती है । एक अनुमान के मुताबिक बिलासपुर के इन शैक्षणिक पुस्तकालयों और शहरों के निजी स्टडी जोन में प्रतिदिन 2500 से अधिक युवा अपनी पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। शासकीय ग्रंथालय की बात करें तो यहां सीजीपीएससी व्यापम और बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कुल पाठकों का लगभग 75 से 80त्न होती हैं।

पुस्तकालयों के डेटा बताते हैं कि जहां एक और साहित्य दर्शन इतिहास और सामान्य ज्ञान की मूल किताबों को पढ़ने के लिए ले जाने वाले पाठकों की संख्या में पिछले 5 वर्षों से 30% की गिरावट आई है वही ई जनरल्स वाई-फाई और डिजिटल लाइब्रेरी और शांत सिटिंग स्पेस की मांग में 50त्न से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

परीक्षा केंद्रित पढ़ाई बनाम ज्ञान का विस्तार :-

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आज का युवा केवल परीक्षा में पास होने के लिए ही ग्रंथालयों का उपयोग करता है। ज्ञान की विस्तार और पढ़ने की ललक धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है ।आज की युवा पीढ़ी में पन्नों को पलटने नोट्स बनाने और मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति कम हो गई है।

समाधान :- समाज और युवा पीढ़ी को बौद्धिक रूप से रचनात्मक विकास करने के लिए पढ़ने को परीक्षा में पास होने के दबाव से मुक्त करना होगा-

मोहल्ला स्तर पर वाचनालय :- शहर के विभिन्न वार्डों में नगर निगम के सहयोग से कम्युनिटी रीडिंग रूम शुरू किया जाना चाहिए जहां बच्चों और बुजुर्गों की पसंद की किताबों का संग्रह और समाचार पत्र की व्यवस्था भी हो । इस तरह एक स्थान पर युवाओं बच्चों और बुजुर्गों का संगम और आपसी वार्तालाप भी बढ़ेगा।

पुस्तकालय का जीवंत होना :- पहले पुस्तकालयों में पुस्तकों के संग्रह पर ही जोर दिया जाता था परंतु आज के दौर में इसे रोचक बनाने के लिए वैचारिक विमर्श पुस्तक समीक्षा जैसे केंद्र भी होने चाहिए ।

बचपन से आदत :- स्कूलों में लाइब्रेरी पीरियड को अनिवार्य और मनोरंजक बनाया जाना चाहिए ।उसे, होमवर्क करने या इनकंप्लीट वर्क को करने या दंड देने के तौर पर पुस्तकालय भेजने का जरिया नहीं बनना चाहिए बल्कि उन्हें नई-नई किताबों के साथ दोस्ती कैसे की जाए इस तरफविचार करते हुए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें किताबों के साथ रूबरू करना चाहिए।

किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती वे संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाती हैं । जब तक हम किताबों से दोबारा नाता नहीं जोड़ते तब तक एक वैचारिक रूप से मजबूत समाज का निर्माण संभव नहीं है ।इंटरनेट के इस शोर में हमें किताबों के मोहक सुकून को पहचानने की आवश्यकता है और अपने शहर के पुस्तकालय को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है।

डॉ. निधि गुप्ता
एम. लिब. (न्यायिक मामलों की विशेषज्ञ आम आदमी और मध्यम वर्ग की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता

अदालत में आश्वासन, जंगल में मौत

हाथियों के लिए क्यों नहीं सुरक्षित हुईं बिजली लाइनें?

राजन कुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मौतें अब केवल वन्यजीवों के लिए खतरा नहीं रह गई हैं, बल्कि बिजली व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हाथी प्रभावित इलाकों में बिजली लाइनों की सुरक्षा को लेकर किए गए दावों और जमीन पर मौजूद हालात में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। अदालतों में नियमों के पालन का भरोसा दिलाने वाले विभागों की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं।

रायगढ़ और धरमजयगढ़ वनमंडल के जंगलों में बिजली के झूलते तार और असुरक्षित लाइनें हाथियों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता नितिन सिंघवी की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई ऐसे स्थान अब भी मौजूद हैं, जहां बिजली लाइनों को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों और विभागीय स्तर पर चिन्हित किए गए खतरनाक स्थानों के बावजूद सुधार कार्य अधूरे पड़े हैं।

हाथी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली लाइनों की ऊंचाई और सुरक्षा को लेकर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में बिजली के तार इतने ऊंचे होने चाहिए कि हाथी अपनी सूंड उठाने पर भी करंट की चपेट में न आए। इसके लिए तारों की ऊंचाई 12 से 15 फीट तक रखने का प्रावधान है। लेकिन रायगढ़ वनमंडल में 51 और धरमजयगढ़ में 58 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां बिजली के तार अब भी खतरनाक स्थिति में हैं।

इन लापरवाहियों का सबसे भयावह उदाहरण घरघोड़ा क्षेत्र के चुहकीमार नर्सरी में सामने आया था, जहां 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक साथ तीन हाथियों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और बिजली कंपनी तथा वन विभाग को मिलकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी कई इलाकों में स्थिति जस की तस बनी हुई है।

अब मामला केवल पुराने तारों तक सीमित नहीं है। हाथी प्रभावित क्षेत्र धनवादा में 33 केवी बिजली लाइन बिछाने को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि नई लाइन के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करते हुए पुराने 11 केवी लाइन के खंभों पर ही 33 केवी लाइन डाल दी गई। न नए खंभे लगाए गए और न ही सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। खुले तारों वाली यह लाइन भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हाथी जैसे बड़े वन्यजीवों के लिए बिजली की खुली लाइनें सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। हाथी अक्सर भोजन और पानी की तलाश में जंगलों से लगे गांवों और खेतों की ओर जाते हैं। ऐसे में यदि रास्ते में कम ऊंचाई वाली बिजली लाइनें मौजूद हों तो हादसे की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

बिजली लाइनों से हाथियों की मौत रोकने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 8 जून 2023 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें संरक्षित क्षेत्रों और हाथी कॉरिडोर में 33 केवी या उससे कम क्षमता वाली बिजली लाइनों को भूमिगत करने सहित कई सुरक्षा उपायों की बात कही गई थी। अदालत में ऊर्जा विभाग के तत्कालीन विशेष सचिव सुनील कुमार जैन ने भी स्वीकार किया था कि 23 फरवरी 2024 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा गया था।

इसके बावजूद मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों द्वारा ऐसी गाइडलाइन की जानकारी नहीं होने की बात सामने आना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि विभाग के शीर्ष स्तर से निर्देश जारी हो चुके थे, तो फिर निचले स्तर तक इसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंची? और यदि जानकारी थी तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया?

हाथियों की मौत के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी तय कब होगी। वन्यजीव संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने वाले राज्य में यदि बिजली लाइनों की लापरवाही से हाथियों की जान जाती है तो इसे केवल दुर्घटना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालतों के निर्देशों और विशेषज्ञों की चेतावनियों के बाद भी यदि व्यवस्था नहीं सुधरती, तो यह प्रशासनिक विफलता का गंभीर उदाहरण बन जाता है।

छत्तीसगढ़ में हाथियों का बढ़ता दबाव पहले ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा रहा है। ऐसे में बिजली कंपनियों और वन विभाग की छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब जरूरत केवल जांच और रिपोर्ट की नहीं, बल्कि उन अधिकारियों और व्यवस्थाओं की जवाबदेही तय करने की है, जिनकी लापरवाही से जंगलों में गजराजों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है।

एक नारी घर को स्वर्ग बना देती है: कविता प्राण लहरे

वक्ता मंच द्वारा 100 महिलाएं सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति, अपराध व मृत्यु भोज जैसी अनेक अप्रासंगिक प्रथाओं को रोकने महिलाये आगे आए। आप अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ कराते भी सिखाये, जिससे वे महिलाओ पर जारी हिंसा की स्थिति में आत्मरक्षा भी कर सके। एक नारी घर को स्वर्ग बना देने के लिए काफी है। सभी नारियां ठान ले तो प्रदेश को नशामुक्त किया जा सकता है। उक्त विचार बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे ने व्यक्त किए। वे वक्ता मंच एवं जन एकता फाउंडेशन द्वारा राजधानी में आयोजित अग्रगामी महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी गुरुशरण पाल गरचा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ मनीषा बी सिन्हा, डॉ नलिनी मढरिया, डॉ करुणा कुर्रे, डॉ प्राची भट्टर, डॉ रत्ना अग्रवाल, पंडित पी के तिवारी, राजकुमार धर द्विवेदी एवं अजीत कुकरेजा उपस्थित थे। वक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश पराते ने जानकारी दी है कि बाल प्रतिभाओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समारोह का आरंभ हुआ।

इस वर्ष सांप्रदायिक सौहार्द्र,थियेटर, फिल्म, जन जागरण, खेल, शिक्षा, चिकित्सा, विधिक सहायता, पत्रकारिता, व्यवसाय, साहित्य, कला, संस्कृति, लोक कला, पुलिसिंग एवं प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही महिलाओं का इस सम्मान हेतु चयन किया गया था। अतिथियों ने इस अवसर पर कहा कि सम्मानित हो रही महिलाओं के कार्यों से समाज में आशा, विश्वास और परिवर्तन का दीप जल रहा है। अतिथियों ने कहा कि वक्ता मंच ने अपनी 3 दशकों की यात्रा में सेवा, संवेदना और संस्कार के नए अध्याय लिखे है। वक्ता मंच केवल संस्था नहीं वरन सामाजिक चेतना, वैचारिक संवाद और जन जागरण का एक सशक्त मंच है। कार्यक्रम के दौरान मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर उच्च व्यवसायों मे संलग्न महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 100 महिलाओं को अग्रगामी महिला अवार्ड एवं सम्मान पत्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित सारंगढ़ की हीरादेवी निराला को वर्ष 2026 की भाग्यशाली महिला का अवार्ड प्रदान किया गया। आज इस अवसर पर राजेश पराते, शुभम साहू,विवेक बेहरा, मनीष अवस्थी, ज्योति शुक्ला, पूर्णेश डडसेना, धनेश्वरी नारंग, उमा स्वामी, राजाराम रसिक, दुष्यंत साहू, हेमलाल पटेल, लक्ष्मी नारायण लहरे, देव मानिकपुरी, डॉ इंद्रदेव यदु, अखिलेश तिवारी सहित टीम वक्ता मंच के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। वक्ता मंच के संयोजक शुभम साहू द्वारा प्रस्तुत आभार प्रदर्शन के साथ समारोह सम्पन्न हुआ। आज सम्मानित होनेवाली महिलाओं में रविंदर कौर भांबरा, स्वीटी सलूजा, आफताब बेगम, डॉ आकांक्षा दुबे, सीमा पांडेय, अनुराधा दुबे, डॉ मान्या ठाकुर, अचला श्रीवास्तव, रूपल पांडे, जया सिंह, अदिति साहू, अर्पिता बेडेकर, रतनजीत कौर, आरजू मीर, अनुभूति श्रीवास्तव, डॉ विधा सिंह राठौर, टिकेश्वरी खटकर, कुंती तेता, हिना देशपांडे , नेहा यादव, रश्मि दुबे सहित 100 महिलाएं शामिल है।

मौत के बाद नहीं होगी वसूली!

भ्रष्टाचार मामलों में कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राह

रायपुर। सरकारी सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी पर चल रही विभागीय जांच अब उसकी मृत्यु के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने से पहले हो जाती है, तो उसके खिलाफ चल रही पूरी प्रक्रिया स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

इस निर्णय का सबसे बड़ा असर उन मामलों पर पड़ेगा, जिनमें कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या सरकारी धन के नुकसान के आरोप लगे थे और उनकी मृत्यु के बाद भी जांच लंबित चल रही थी। अब ऐसे मामलों में कर्मचारी के आश्रितों को राहत मिलेगी और पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि सहित अन्य स्वत्वों के भुगतान में आने वाली बाधाएं दूर हो सकेंगी।

दरअसल, वर्ष 2012 में जारी एक परिपत्र को लेकर अलग-अलग विभागों में अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही थी। कई विभागों में कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी विभागीय जांच जारी रखी जा रही थी। इसके कारण मृत कर्मचारियों के परिवारों को लंबे समय तक प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझना पड़ता था। कई मामलों में पेंशन और अन्य भुगतान रोक दिए जाते थे, जिससे आश्रितों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

अब सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद विभागीय कार्रवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। जांच की प्रक्रिया उसी समय समाप्त मानी जाएगी और विभागों को मृत कर्मचारी के परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी होगी।

हालांकि सरकार ने इस राहत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। यदि कर्मचारी के जीवित रहते ही विभागीय जांच पूरी हो चुकी थी और सक्षम अधिकारी द्वारा वसूली या दंड का अंतिम आदेश जारी किया जा चुका था, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। यानी यदि रिकवरी का आदेश कर्मचारी की मृत्यु से पहले पारित हो चुका है, तो नियमानुसार उसकी वसूली की जा सकेगी।

इसका मतलब यह है कि केवल लंबित जांच या अधूरी कार्रवाई वाले मामलों में ही आश्रितों को राहत मिलेगी। लेकिन जहां कर्मचारी के खिलाफ आरोप साबित हो चुके थे और विभाग ने अंतिम निर्णय ले लिया था, वहां सरकारी धन की वसूली का रास्ता खुला रहेगा। सरकार के इस फैसले को मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय तक चलने वाली विभागीय जांच के कारण कई परिवार वर्षों तक अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रहते थे। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय और भुगतान की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस.के. सिंह की ओर से जारी यह परिपत्र प्रदेश के सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार के इस कदम से जहां मृत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत मिलेगी, वहीं विभागों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामलों में भी स्पष्ट नियम लागू हो गया है कि कार्रवाई तभी तक जारी रहेगी, जब तक कर्मचारी जीवित है और प्रक्रिया अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है।

चिंगरापगार वाटरफॉल में टूरिस्ट-लोगों में मारपीट, गाड़ियां तोड़ीं

- **एंट्री को लेकर विवाद, युवक बोला- हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, डरते नहीं, ग्रामीणों ने पीटा**

गरियाबंद। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चिंगरापगार में पार्किंग और एंट्री को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने युवकों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक युवक खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए कहता नजर आ रहा है कि हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। वहीं, कुछ अन्य युवक पुलिस से बहस करते भी दिखाई दे रहे हैं।

आरोप है कि युवक खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए पार्टी का नाम लेकर ग्रामीणों और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना गरियाबंद थाना क्षेत्र की है।

दोपहर के बाद जबरन अंदर जाने की कोशिश: जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर 3 बजे के बाद पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है। इसके बावजूद दुर्ग से आए कुछ युवक जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां व्यवस्था संभाल रही स्थानीय समिति के सदस्यों ने उन्हें रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई।

बहस के बाद हुई मारपीट: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही देर में बहस मारपीट में बदल गई। आरोप है कि बाहरी युवकों ने समिति के सदस्यों के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए पुलिस से बहस करते दिखाई दे रहे हैं।

आत्मानंद स्कूल में चीखने-चिल्लाने लगीं छात्राएं, हाथ-पैर अकड़े

रोने लगी, फिर बेहोश हुईं, 3 दिन में 8 केस, 9वीं की स्टूडेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल

भिलाई। आत्मानंद स्कूल में सोमवार को 2 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक छात्रा अजीब हरकतें करने लगी और चीखने-चिल्लाने लगी। उसके हाथ-पैर अकड़ने लगे। आंख से आंसू निकलने लगे। इसके बाद दोनों छात्राएं बेहोश हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। एक छात्रा को सिकलिन की समस्या निकली, वहीं दूसरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई।

बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में 8 केस सामने आए हैं। मामला खम्हरिया स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल (सेजेस) का है। कक्षा 9वीं-ए में 3 दिन पहले 5 छात्राएं अचानक चीखने-चिल्लाने लगी थी। अस्पताल ले जाते ही नॉर्मल हो गई। अगले दिन भी 2 छात्राएं इसी तरह चीखने-चिल्लाने और रोने लगी थी। उन्हें भी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही छात्राओं की काउंसलिंग कराने के लिए साइकोलॉजिकल टीम भी बुलाई गई है।

9 जुलाई से शुरू हुआ मामला: स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता दीवान ने बताया कि पहली घटना 9 जुलाई को शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच हुई। एक छात्रा को अचानक चक्कर आया, जिसके बाद उसे स्टाफ रूम ले जाया गया। कुछ ही देर बाद दूसरी छात्रा जोर-जोर से चीखने लगी। दोनों के परिजनों को बुलाकर उन्हें घर भेज दिया गया।

हाथ-पैर अकड़ गए, बोलने में भी हो रही थी दिक्कत: प्रिंसिपल के अनुसार, उसी दिन 3 अन्य छात्राएं भी क्लास में बेहोश हो गईं। उनके हाथ-पैर अकड़ गए, आंखों से पानी निकलने लगा और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं। पहले 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। लेकिन समय लगने की जानकारी मिलने पर छात्राओं को ऑटो से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान?

- **कर्मचारियों को मिला 31 जुलाई तक फैसला लेने का मौका**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने क्रमोन्नति योजना को वित्त विभाग के समयमान वेतनमान में समाहित करने के संबंध में विकल्प देने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे पहले यह अवधि 9 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दरअसल, क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक का चयन करने को लेकर कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अलग-अलग विभागों में पद संरचना और सेवा नियमों में अंतर होने के कारण कई कर्मचारी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके लिए कौन-सा विकल्प भविष्य में अधिक लाभकारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इसी समस्या को देखते हुए 6 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने सरकार के सामने यह मुद्दा रखा था कि कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय

दिया जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य के वेतन और सेवा लाभों को प्रभावित कर सकता है।

सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करते हुए अब अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड, वेतन लाभ और भविष्य में मिलने वाले आर्थिक फायदे को समझने के बाद निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका लाभ केवल निर्धारित संवर्गों के कर्मचारियों को ही मिलेगा। इनमें शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, निर्माण विभागों और अन्य विभागों के उपअभियंता तथा वन विभाग के वनक्षेत्रपाल शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पात्र कर्मचारी क्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। एक बार विकल्प चुनने के बाद इसका असर कर्मचारी के भविष्य के वेतन निर्धारण और सेवा लाभों पर पड़ेगा।

प्रकाशक एवं मुद्रक सुभाष मिश्रा द्वारा स्वामी अभिव्यक्ति प्रकाशन प्रा.लि. के लिए मिशन मीडिया प्रा.लि., रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं एचआईजी 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित।
प्रधान संपादक- सुभाष मिश्रा, सलाहकार संपादक-भालचंद्र जोशी, स्थानीय संपादक-विवेक मिश्रा, आरएनआई रजि. नं.-52143/91, * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।